सांध्य दैनिक

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534

डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./ दुर्ग /94/2023-25

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 15 अंक - 240 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, गुरुवार 13 जून 2024 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क वापस, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- 23 जून को फिर से होगी परीक्षा

नईदिल्ली। नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से नीट-यूजी 2024 के 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस अंक देने का निर्णय वापस ले लिया गया है।

ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इसके नतीजे 30 जून को आएंगे। ऐसे में अब छात्रों के पास विकल्प होगा कि वे फिर से परीक्षा देना चाहते हैं या बिना ग्रेस मार्क के काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं। मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह नीट-यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी। हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है।

केंद्र ने कोर्ट से क्या कहा?

सरकार-एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1,563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई, जिन्हें नीट-यूजी में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए 'ग्रेस मार्क्स' की समीक्षा का जिम्मा दिया गया। समिति ने 1,563 नीट-यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का फैसला लिया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे।

कोर्ट ने एनटीए की दलील को रिकॉर्ड में लिया

सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए के इस दलील को रिकॉर्ड में लिया कि 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा आज ही अधिसूचित की जाएगी और इसे संभवत: 23 जून को आयोजित किया जाएगा। परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे, ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो।

खास-खबर

पेट्रोलियम टैंकर ने बाइक सवार को कुचला

रायपुर। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले नागपुर कोलकाता नेशनल हाईवे में पेट्रोलियम टैंकर ने बाइक सवार को बुरी तरह कुचल दिया है। यह हादसा रायपुर से सटे आरंग इलाके में हुआ। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि टैंकर का टायर मृतक के कंधे के ऊपर से गुजरा। जिससे बॉडी टैंकर के निचले हिस्से में फंस गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बॉडी को बाहर निकाल लिया। इस मामले में पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। हादसा गुरुवार सुबह 9 बजे के करीब हुआ। मृतक की पहचान परस निषाद (50) के तौर पर हुई है। वो बरबसपुर महासमुंद का रहने वाला है। वह खेती-किसानी का काम करता था। बाइक से वह अकेले आरंग से वापस अपने घर महासमुंद की ओर जा रहा था। इस दौरान आरंग के पारागांव के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार पेट्रोलियम टैंकर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही टैंकर का अगला टायर परस के कंधे को कुचलते हुए आगे निकल गया। इससे लाश टैंकर के निचले हिस्से में फंस गई। ब्रेक लगाने के बावजूद टैंकर ने 100 मीटर तक लाश को घसीट दिया इस दौरान मृतक की बाइक भी चकनाचूर होकर टैंकर के सामने हिस्से में फंसी रही। इस एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आरंग पुलिस ने मृतक की लाश को आसपास के स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला। फिर उसे CHC आरंग भेज दिया गया। घटना के बाद टैंकर का ड्राइवर अजय यादव मौके से फरार हो गया था। जिसे आरंग पुलिस की टीम ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर पीछा कर हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मृतक के घर वालों को सूचना दे दी है।

देशभर में छत्तीसगढ़ की धूम 'संवर रहा छत्तीसगढ़' कर रहा ट्रेंड

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 6 माह पूरे, समग्र विकास पथ पर बढ़ रही सरकार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के छह महीने पूरे होने पर संवर रहा छत्तीसगढ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (एक्स) पर ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग के तहत लोग सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों की तारीफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने 6 महीनों में ही छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, माओवादी समस्या का निदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सोशल मीडिया पर जनता के सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि सीएम साय के त्वरित निर्णय-सख्त प्रशासन को सराहा जा रहा है और संवरते छत्तीसगढ़ के प्रति लोग आश्वस्त हैं।

बता दें छत्तीसगढ़ में पिछले साल नवंबर दिसंबर में हुए चुनाव के बाद भाजपा ने कांग्रेस को पटकनी देते हुए सरकार में वापसी की। छत्तीसगढ़ सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजना

महतारी वंदन योजना से लेकर किसानों को धान का 3100 रुपए समर्थन मूल्य सहित विभिन्न योजनाओं को सराहा जा रहा है। सरकार के 6 माह पूरे होने पर योजनाओं की समीक्षा भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के 6 माह पूरे होने पर संवर रहा छत्तीसगढ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (एक्स) पर ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर हजारों की संख्या में लोग छत्तीसगढ़ के विकास की सराहना कर रहे हैं।

सीएम साय ने की नए विधानसभा भवन व अन्य निर्माण की समीक्षा

गुरुवार को मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह के साथ नवा रायपुर में बन रहे विधानसभा के नवीन भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई बैठक में नवा रायपुर में विधानसभा भवन सहित विधायक विश्रामगृह एवं विधानसभा के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण के प्रगति की जानकारी ली गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरूण साव, स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी बैठक में उपस्थित रहे।

नए विधानसभा भवन नई सुविधाओं से होगा लैस

नवा रायपुर में विधानसभा भवन बनाने की तैयारी चार साल पहले शुरू की गई थी। विधानसभा भवन को आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है। ताकि सदस्यों को सभी तरह की सुविधाएं मिल सकें। अलग-अलग कैटेगरी व पद के हिसाब से कार्यालयों एवं कमरों का निर्माण किया जाएगा। पक्ष-विपक्ष के विधायकों के बैठने के लिए विशेष सीट बनाई जाएंगी। अलग-अलग दीर्घा का निर्माण होगा। विधानसभा के नए भवन में पार्किंग का सिस्टम भी अलग रहेगा। कैफेटेरिया और कैंटीन भी बनाए जाएंगे।

8 एकड़ में बन रहा मुख्यमंत्री निवास

नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के साथ अफसरों के आवासों का भी निर्माण हो रहा है। इसी कड़ी में सीएम साय के लिए नया बंगला बन कर लगभग तैयार हो गया है। सुरक्षा ऑडिट सहित कुछ कार्य और शेष हैं। नवा रायपुर के सेक्टर-24 में लगभग 8 एकड़ में बने सीएम हाउस की लगात करीब 65 करोड़ बताई जा रह है। कई तरह की आधुनिक सुविधाएं से लैस यह बंगला पूरी तरह हाईटेक होगी। नवा रायपुर में सीएम हाउस और मंत्रियों के निवास के साथ ही नया राजभवन और विधानसभा भवन भी बन रहा है। सभी भवनों को 2022 के अंत तक तैयार हो जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ समय के लिए इन भवनों का निर्माण कार्य रुक गया था। अफसरों के अनुसार भवनों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। कुछ भवनों में फिनिशिंग का काम अंतिम दौर में चल रहा है।

दुर्ग-विशाखापट्टनम के बीच दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन

रायपुर। दुर्ग से विशाखापट्टनम तक वंदे-भारत एक्सप्रेस इसी महीने से दौड़ने लगेगी। इसकी तैयारी में रेलवे मंडल जुटा हुआ है और रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की थी। इस बीच आचार संहिता लगने से इसकी अधिकृत घोषणा नहीं हो पाई। अब आचार संहिता हटने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी जोर-शोर से की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्?णुदेव साय ने रेलमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा था कि दुर्ग, भिलाई, चरोदा, कुम्हारी और राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में आंध्र प्रदेश के मूल निवासी रहते हैं।

अधिकांश लोग आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। वह अक्सर अपने पैतृक निवास और सामाजिक कार्यों में शामिल होने के लिए विशाखापट्टनम और उसके आसपास के क्षेत्रों में आते-जाते रहते हैं, लेकिन कम समय में सीधी रेल सुविधा का अभाव है। साथ ही विशाखापट्टनम उच्च शिक्षा, पर्यटन और व्यावसायिक केंद्र है। यहां के स्कूलों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दुर्ग-भिलाई और रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के अनेक बच्चे पढ़ते हैं। यहां बंदरगाह होने के कारण कोयला, जिप्सम, कोक, अनाज और अन्य वस्तुओं का आयात-निर्यात होता है इसकी वजह से लोगों को विशाखापट्टनम बार-बार आना-जाना पड़ता है। वंदे भारत एक्सप्रेस चलने से सभी लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी।

दुर्ग से वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह छह बजे निकलेगी और दोपहर 2.30 बजे विशाखापट्टनम पहुंचेगी। दोपहर 3.15 को विशाखापट्टनम से छूटेगी साढ़े आठ घंटे में 565 किलोमीटर की दूरी तय कर रात 11.50 को दुर्ग स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन दुर्ग से रायपुर, लखोली, महासमुंद, खरियार-रोड, कांटा-भांजी, टिटलागढ़, सिंगापुर-रोड, रायगढ़ा, पार्वतीपुरम् और विजयानगरम होते हुए विशाखापट्टनम पहुंचेगी। दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन को महज साढ़े आठ घंटे का ही समय लगेगा।

दुर्ग से दूसरी सीधी ट्रेन, रायपुर से गुजरेगी

विशाखापट्टनम के लिए वंदे-भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से दुर्ग से विशाखापट्टनम जाने के लिए दूसरी सीधी ट्रेन मिलेगी। इन दिनों दुर्ग-विशाखापट्टनम् वाल्टेयर एक्सप्रेस चल रही है। यह ट्रेन 48 स्टेशनों में रुकती है। इसमें करीब 16 घंटे का सफर होता है। इस तरह वंदे-भारत एक्सप्रेस में लगभग आधे समय में यानी 8.30 घंटे में विशाखापट्टनम पहुंच सकेंगे और उसी दिन काम पूरा करके वापस लौट भी लौट सकेंगे। इसकी औसत गति 66.47 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी।

पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के CM के रूप में ली शपथ, उप मुख्यमंत्री बने चाउना मीन

ईटानगर। भाजपा नेता पेमा खांडू ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं, चाउना मीन ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। खांडू के साथ-साथ 11 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल केटी परनाइक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में शपथ दिलाई। एक दिन पहले ही खांडू को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था।

केंद्रीय प्रर्यवेक्षक भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और तरुण चुघ बुधवार को ईटानगर पहुंचे थे। इस दौरान, उन्होंने भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई और विधायक दल का नेता चुना। शाम को खांडू चुघ और कई विधायकों के साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि) केटी परनायक से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे। उन्होंने इस दौरान सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने खांडू और उनके मंत्रियों को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया। चुघ ने राजभवन में मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बियुराम वाघ ने मुख्यमंत्री के रूप में खांडू के नाम का प्रस्ताव रखा था। पार्टी के सभी 46 विधायकों ने इसका समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की सराहना करते हुए, खांडू ने भाजपा में विश्वास जताने और उसे लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया।

मोनपा जनजाति से ताल्लुक रखते हैं पेमा खांडू

पेमा खांडू का जन्म 21 अगस्त, 1979 को तवांग में हुआ था। चीन की सीमा से सटे तवांग जिले के ग्यांगखर गांव से ताल्लुक रखने वाले पेमा खांडू मोनपा जनजाति से आते हैं। उन्होंने तवांग के बोम्बा में सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वर्ष 2000 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि हासिल की। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा।

नीट घोटाला और पारदर्शिता

श्रीकंचनपथ

नीट घोटाला करोड़ों रुपए का खेल है। कम से कम गोधरा जिला कलेक्टर की जांच तो यही बताती है। कलेक्टर के इशारे पर मारे गए छापे में नीट परीक्षा केन्द्र के एक शिक्षक की कार से 7 लाख रुपए नकद बरामद किये गये। गिरोह ने 26 बच्चों को नीट-यूजी 2024 की मेरिट लिस्ट में लाने का ठेका लिया था। इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी से 10 लाख रुपए लिये जाने थे। अर्थात 26 बच्चों से ली जाने वाली राशि लगभग ढाई करोड़ थी। इस बार नीट में 67 बच्चे पूर्णांक लेकर आए हैं। अर्थात उन्हें 720 में से 720 मिले हैं। रैकेट का मास्टरमाइंड वदोदरा में कोचिंग सेंटर चलाने वाला परशुराम रॉय था जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता आरिफ वोरा तथा शिक्षक तुषार भट्ट की मदद से इसे चलाता था। जिन 26 विद्यार्थियों ने पैसे दिये थे वो सभी जय जलाराम स्कूल के दो अलग-अलग केन्द्रों में परीक्षा दिला रहे थे। सौदा यह था कि बच्चे उन प्रश्नों को हल नहीं करेंगे जिनका उत्तर उन्हें नहीं मालूम। उनकी तरफसे यह काम परीक्षा के बाद विषय विशेषज्ञ करेंगे। विद्यार्थियों ने परशुराम रॉय और तुषार भट्ट को 2.82 करोड़ रुपए के चेक देने की बात भी कही है। यह मामला नीट का आयोजन करने वाली संस्था एनटीई को क्लीन चिट देती है। एनटीई का दावा है कि परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बरती गई और इसमें पर्चा लीक नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर पर्चा परीक्षा शुरू होने के बाद आया जिसे पेपर लीक नहीं कहा जा सकता। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। रांची के एक परीक्षार्थी ने बताया कि उसके पिता के एक दोस्त सिकंदर ने 4 मई की रात को एक प्रश्न पत्र लाकर उसे दिया था जिसे उसने रट लिया। 5 मई को जब वह परीक्षा देने गया तो वही प्रश्न आए। समस्तीपुर के अनुराग और दानापुर के आयुष ने भी लगभग यही बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक पर्चा 4 मई को दिया गया जिसे रट कर वे परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा में वही प्रश्न पूछे गए थे। जाहिर है कि एनटीई का दावा खोखला है। परीक्षा माफिया सक्रिय था। अब आते हैं मूल विषय पर। देश के लाखों विद्यार्थी कक्षा दसवीं से ही खाना-पीना, खेलना-कूदना छोड़कर दिन रात नीट की तैयारी करते हैं। यह तैयारी वो अकेले नहीं करते बल्कि उनका पूरा परिवार इसके लिए कुर्बानियां देता है। इस साल भी 24 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दिलाई थी। 4 जून को जब परिणाम आए तो पता चला कि कुछ बच्चे ग्रेस मार्क्स से मेरिट में आ गए। 67 बच्चों को पूर्णांक मिला है। एक ही केन्द्र से 6-6 बच्चे पूर्णांक वाले निकल आए। कुछ बच्चों को ऐसे अंक मिले हैं जो मार्किंग स्कीम से मेल नहीं खाते। यदि अब भी रट लगाते रहे कि इस सरकार में घोटाले नहीं होते तो यही कहना होगा कि इस सरकार में घोटाले सामने नहीं आते।

संपादकीय

दो नई सरकारें

एन चंद्रबाबू नायडू ने आज चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक नए दौर की शुरुआत की, वहीं ओडिशा में मोहन चरण मांझी ने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर एक नया इतिहास लिख दिया है। आंध्र प्रदेश में जहां तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व में भाजपा की सहयोगी भूमिका से गठबंधन सरकार बनी है, तो वहीं ओडिशा में भाजपा ने अकेले दम पर सरकार बनाई है।

> चंद्रबाबू नायडू भारत में सूचना-प्रौद्योगिकी के नाम पर पहचान रखने वाले नेता हैं। मुख्यमंत्री के रूप में जब उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने हैदराबाद को 'आईटी हब' के रूप में बदल दिया, अब जब वह फिर मुख्यमंत्री बने हैं, तब उन्हें आईटी क्षेत्र में एक नई क्रांति के लिए काम करना चाहिए। भारत में, वह भी आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में आईटी के क्षेत्र में ज्यादा निवेश, नवाचार व सरकारी स्तर पर ज्यादा सहूलियत की जरूरत है।

चंद्रबाबू को एक नया आंध्र बनाने के लिए काम करना चाहिए। अमरावती में राजधानी बनाने की योजना पर वह बेशक काम करें, पर उन्हें रोजगार और प्रदेश के बुनियादी विकास के लिए ज्यादा सोचना चाहिए।

आंध्र प्रदेश के नए मंत्रिमंडल में संभावना के अनुरूप ही तेदेपा के 21 विधायकों, जन सेना के तीन विधायको और भाजपा के एक विधायक को शपथ दिलाई गई है। खास यह भी है कि आंध्र में इस बार पहली बार चुनाव जीतने वाले आठ विधायकों को मंत्री बनाया गया है। पहली बार चुनाव जीते लोकप्रिय अभिनेता पवन कल्याण ने भी सहर्ष मंत्री पद स्वीकार किया है, जिससे कला क्षेत्र में भी हलचल है। वैसे चंद्रबाबू नायडू भी महान अभिनेता एनटी रामाराव की विरासत ही संभाल रहे हैं। चंदबाबू ने कसम खाई है कि वह राज्य में केवल एक राजधानी बनाएंगे, तो उन्हें ध्यान रखना होगा कि भ्रष्टाचार के दाग न लगें। नई राजधानी का निर्माण एक बड़ी योजना है, उसे ईमानदार हाथों से पूरा होना चाहिए। चंद्रबाबू के लिए एक बड़ी चुनौती अपने किए वादे को पूरा करना है। ज्यादातर विश्लेषक यही मानते हैं कि पिछली बार भी वह अपने वादे न निभाने की वजह से ही हारे थे। दरअसल, दक्षिण में भांति-भांति की मुफ्त योजनाएं घोषित होती हैं, जिनको पूरा करना व्यावहारिक रूप से आसान नहीं होता। जनता ने चंद्रबाबू की राजनीति पर भरोसा जताया है और इस भरोसे का कायम रखना नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है।

उधर, ओडिशा के भी कायाकल्प का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला है। नवीन पटनायक के समय यह राज्य लगभग ठहर गया था, हर तरह के संसाधनों के बावजूद ओडिशा उतना आगे नहीं बढ़ पाया, जितना उसके कुछ अन्य पड़ोसी राज्य बढ़ गए। छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ गया, बंगाल भी ठीक स्थिति में है, बिहार की जीडीपी भी तेजी से बढ़ रही है, मगर ओडिशा का हाल बुरा था, तो लोगों ने लगभग ढाई दशक बाद नवीन पटनायक को किनारे कर दिया। अब बागडोर भाजपा के हाथों में है, तो इसका सीधा अर्थ है कि ओडिशा के लोग तेज तरक्की चाहते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। अगर केंद्र सरकार का पूरा साथ मिला, तो ओडिशा वाकई बड़ी तेजी से देश की मुख्यधारा में आ सकता है। भाजपा में ओडिशा को लेकर उत्सव का माहौल है, पार्टी में जगन्नाथ शब्द इन दिनों बहुत प्रिय हो गया है। पार्टी के नेता अगर मानते हैं कि उन्हें भगवान जगन्नाथ की भूमि की सेवा का अवसर मिला है, तो यह अवसर हाथ से जाना नहीं चाहिए।

कड़ी कार्रवाई के साथ सबक भी लेना चाहिए...

सुनील दास

कोई भी बड़ी और बुरी घटना होती है तो वह अचानक नहीं होती है, उसकी तैयारी की जाती है,उसके बाद भीड़ की आड़ में वह सब किया जाता है जो कुछ लोग ऐसे नहीं कर पाते है। यह अराजक व हिंसक तत्व होते है। यह भीड़ का फायदा उठाने वाले होते हैं। जहां भी भीड़ लगती है, वह भीड़ को उकसाकर वह सब करवा लेते हैं जो वह करवाना चाहते हैं।

अराजक तत्व तो मौका मिलने पर अराजकता फैलाएंगे ही, इसे रोकना तो जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन का काम है। अराजक तत्व क्या करने वाले है,यह पता लगाना पुलिस का काम है, वह समय से पहले पता नहीं लगा पाई और उसी का परिणाम है कि भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने कलेक्टर व एसपी आफिस में भारी तोड़फोड़ कर आग लगा दी। कार्यालयों के परिसर में खड़े सैकड़ों वाहनों को जला दिया। कहीं आग लगाना व वाहनों को जलाना यूं ही अचाकन कोई नहीं कर सकता है, इसके लिए तैयारी करने पड़ती है। कहीं भी आग लगाना होता है तो इसके लिए पेट्रोल व डीजल की जरूरत होती है, उसे ले जाने के लिए जरीकेने की जरूरत होती है। जब भीड़ में ऐसे लोग शामिल थे जिनके पास आग लगाने का पूरा सामान था था तो इसका मतलब है कि अराजक तत्व आग लगाने की तैयारी करके आए थे।

जिला व पुलिस प्रशासन की असफलता यह है कि वह अराजक तत्वों के मंसूबों का समय रहते पता नहीं लगा पाई इसलिए वह आगजनी व तोड़फोड़ को रोक नहीं पाई। यह तो शुक्र है कि दफ्तरों में काम रहे लोगों को आग लगाने से पहले सुरक्षित निकाल लिया गया। बताया जाता है सतनामी समाज इस बात ने नाराज था कि गिरौदपुरी के मानाकोनी धार्मिक स्थल में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की थी। समाज चाहता था कि दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाए, बताया जाता है कि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, समाज के लोग इससे संतुष्ट नहीं थे, वह दोषी लोगों पर कार्रवाई व मामले की जांच की मांग कर रहे थे। कलेंक्ट ने इस मामले में बैठक बुलाकर समाज के लोगों से बात की थी, गृहमंत्री ने घोषणा की थी कि मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी।

समाज के लोगों ने 10 जून को इस मामले में धरना प्रदर्शन करने के लिए अनुमति ली थी। धरना प्रदर्नश के दौरान किसी बात से भीड़ उग्र हुई तो इस स्थिति का फायदा अराजक तत्वों ने उठाया। भीड़ को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं रोक पाई और भीड़ कलेक्टर व एसपी आफिस पहुंच कर वहां आग लगा दी और सैकड़ों वाहनों को जला दिया। इस घटना से पुलिस व जिला प्रशासन को यह सबक लेने की जरूरत है कि वह किसी भी संगठन या समाज को ज्यादा भीड़ वाले आयोजन करने की अनुमति न दे।

जब भी कोई समाज किसी बात से नाराज होता है तो उस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। मामले को जल्द निपटाने का प्रयास करना चाहिए। समाज को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पुलिस व जिला प्रशासन उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। समाज की भी कोशिश होनी चाहिए कि वह ज्यादा भीड़ किसी आयोजन में एकत्र न करे। उतने ही लोगों को आयोजन में बुलाए जिनको नियंत्रित किया जा सके। उसे इसब बात से बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि अराजक तत्व उनके आयोजन में शामिल न हो सकें। जब भी बलौदाबाजार जैसी घटना होती है तो उससे सबक लिया जाना चाहिए और इस घटना के लिए दोषी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वह भविष्य में इस तरह कानून व्यवस्था से खिलवाड़ न कर सकें। किसी कलेक्टर या एसपी आफिर में आग लगाने की हिम्मत न कर सके।

(ये लेखक के विचार हैं)

नजरिया

सुविधा की सियासत में सिर्फ एक हथियार वोटिंग मशीन

नव-निर्वाचित भाजपा सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईवीएम पर टिप्पणी थी, तो विपक्ष पर कटाक्ष, पर मतदान प्रक्रिया पर हमारी राजनीति को भी वह बेनकाब कर गई। मोदी ने कहा कि 4 जून को जब चुनाव परिणाम आ रहे थे, तब उन्होंने किसी से पूछा कि ईवीएम जिंदा है या मर गई? मोदी का कटाक्ष विपक्ष द्वारा एक बार फिर चुनाव के वक्त ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठाए गए सवालों के संदर्भ में था।

राज कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार

वीवीपैट के 100 प्रतिशत मिलान या बैलेट पेपर से मतदान की मांग सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिए जाने के बावजूद चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष लगातार ईवीएम पर आशंकाएं जताता रहा। आरोप था कि संदेहास्पद ईवीएम व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सत्ता पक्ष चुनाव जीतने पर आमादा है, पर परिणामों के बाद इस मुद्दे पर मौन पसर गया। बेशक, चुनाव प्रणाली को संदेह से परे होना चाहिए, मगर उस पर बिना ठोस आधार के सवाल भी नहीं उठाए जाने चाहिए। भारतीय चुनाव प्रक्रिया की साख पूरी दुनिया में है। उस पर देश में ही सवाल उठना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सुखद तस्वीर पेश नहीं करता।

वैसे, विपक्ष में रहते हुए भाजपा भी ईवीएम पर संदेह का शोर मचाने में पीछे नहीं रही। साल 2009 में भाजपा के नेता जीवीएल नरसिम्हा ने ईवीएम की विश्वनीयता पर सवाल उठाते हुए पुस्तक लिखी थी। उसकी भूमिका लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी थी, जो तब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। मामला अदालत तक गया था। 2014 में भाजपा केंद्र की सत्ता में आ गई, तो उसके लिए ईवीएम पवित्र गाय-सी हो गई और विपक्ष में पहुंच गए दलों को उसमें खामियां नजर आने लगीं। मार्च, 2017 में जब पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, तो 13 दलों ने परिणामों पर सवाल उठाया। चुनाव आयोग से शिकायत भी की, पर 2018 के अंत में हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता मिल गई, तो ईवीएम पर विपक्ष मौन हो गया। पिछले साल हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार पर ईवीएम पर उंगली उठाई गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में जीत पर ईवीएम निर्दोष रही।

कुछ ही दिनों बाद दिसंबर में फिर विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' लोकसभा चुनाव में वीवीपैट के 100 प्रतिशत मिलान की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसे खारिज करते हुए डेटा सुरक्षा संबंधी कुछ जरूरी निर्देश चुनाव आयोग को दिए गए। मामला चुनाव प्रक्रिया में जनता के विश्वास से जुड़ा है, इसलिए उसे और अधिक पारदर्शी व विश्वसनीय बनाने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत में सुनवाई आगे भी होगी, मगर उसकी इस नसीहत पर चुनाव आयोग व राजनीतिक दलों को गौर करना चाहिए कि संदेह जताने से जनता के मन में संशय पैदा होता है, जो अच्छा नहीं है। जब छेड़छाड़ के संदेह को साबित करने के लिए आयोग ने राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया था, तब कोई दल नहीं पहुंचा। जिन लोगों ने मतपत्रों से चुनावों का दौर देखा है, उन्हें मतदान केंद्रों पर कब्जे और मतपत्रों की लूट की डरावनी स्मृतियां होंगी, इसलिए नई प्रौद्योगिकी से मुंह मोड़कर उस युग में वापसी की मांग तर्कसंगत नहीं।

यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे यहां ईवीएम अचानक नहीं आ गई। जांच-परख के बाद चरणबद्ध ढंग से अपनाया गया है। देश में ईवीएम का विधिवत इस्तेमाल पहली बार 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर किया गया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पूरे देश में इससे मतदान कराया गया और जीत सत्ता पक्ष की नहीं, विपक्ष की हुई। इस बीच मतदान प्रक्रिया में वीवीपैट समेत कई सुधार भी किए गए हैं। याद रहे कि 2019 के चुनाव में आंध्र प्रदेश के मईदुकुर में ईवीएम और वीपीपैट की गिनती में 14 वोटों का अंतर पाया गया था, तो 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के एक विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम की गिनती से पहले के बजाय बाद में गिने गए बैलेट पेपर हार-जीत के अंतर से ज्यादा रहे। इसलिए चुनाव प्रक्रिया को संदेह से परे रखने के लिए जरूरी सुधार जारी रहने चाहिए। यह जिम्मेदारी सांविधानिक संस्था चुनाव आयोग की ज्यादा है, जिसकी साख पर इतने सवाल पहले कभी नहीं उठे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

वैचारिक मतभेदों को व्यक्त करने का घृणित तरीका

प्रियंका सौरभ

वैचारिक मतभेदों को व्यक्त करने का घृणित तरीका, खासकर जब आप वर्दी पहने हों। 'शर्मिंदगी और हैरानी इस बात की है कि ये काम सीआईएसएफ की सुरक्षाकर्मी ने किया है जो लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं। क्या ये कंगना के खिलाफ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर प्लांड अटैक है। सांसद पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुआ हमला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर एक सुरक्षाकर्मी द्वारा, जिन पर सुरक्षा का जिम्मा होता है। अपनी शिकायत को रखने का और भी सभ्य तरीका होता है।'

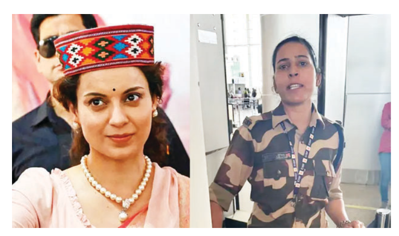

भारतीय राजनीति और सामाजिक जीवन में हम अक्सर इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनते हैं। 'थप्पड़' कहने से हिंसा की गंभीरता कम होती है और हिंसा के शिकार की कमजोरी ज्यादा उजागर होती है। थप्पड़ से किसी की जान नहीं जाती, उसकी निष्कवचता अधिक प्रकट होती है। उसमें किसी योजना की जगह एक प्रकार की स्वत: स्फूर्तता का तत्व होता है। कहा जा सकता है कि थप्पड़ मारने वाले की मंशा सिर्फ नाराजगी का इजहार होता है। राजनीति और सिस्टम (लोकतंत्र या तानाशाही) में विरोध जायज है और यही विरोध तरह तरह के स्वरूपों में हमारे सामने आता रहता है। थप्पड़ या स्याही हमला भारतीय राजनीति में कोई नया किस्सा नहीं है। पहले भी हमारे नेता इन हमलों का दंश झेलते रहे हैं।

इतना ही नहीं कई नेताओं पर जूता उछाले जाने की घटनाएं भी हुई हैं। लोकतंत्र लोगों को विरोध प्रदर्शन की आजादी देता है और लोग विरोध के नए-नए तरीके खोज लाते हैं। कभी विरोध में अंडे, टमाटर फेंके जाते हैं, तो कभी जूते-चप्पल 'कंगना ने किसान आंदोलन के खिलाफ में कुछ बोला तो सीआईएसफ की कांस्टेबल ने आज कंगना पर हमला कर दिया। ये कहां तक उचित है? जो लोग इसे सही ठहरा रहे हैं वे ये समझ लें कि रक्षक को भक्षक नहीं बनना होता है। आपकी व्यक्तिगत सोच और विचारधारा आपकी ड्यूटी के बीच में नहीं आनी चाहिए। देशभर में दर्जनों नेता हैं जो सेना के खिलाफ बोलते आए हैं। कभी सिक्यूरिटी के दौरान किसी सैनिक की भावना उसकी ड्यूटी के बीच आ गई तो ऐसे नेताओं का वहीं हिसाब हो जाएगा। धारा 370, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर कई नेताओ और सेलिब्रिटीज़ के घटिया और भद्दे बयान सबके सामने हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर हर सुरक्षाकर्मी सिक्यूरिटी के दौरान अपनी भवनाएं दिखाने लगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग कैसे इस महिला के एक्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं।

क्या लोग ये भूल गए कि ऐसे ही दो सुरक्षा कर्मचारियों की भावनाएं उनकी ड्यूटी के बीच आ गई थी जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की हत्या हुई। हिंसा की भर्त्सना बिना शर्त जब तक न की जाएगी, जब तक उसके लिए कोई औचित्य तलाशा जाता रहेगा और जब तक वह विचारधारा के आधार पर सही या गलत मानी जाएगी, उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। संचार माध्यमों द्वारा हिंसा को नयनाभिराम बनाकर अगर उपभोग्य बना दिया गया तो वह फिर बार-बार 'अदा' की जाएगी और अपनी भयावहता भी खो बैठेगी। वह लोकतंत्र का सबसे सबसे खतरनाक क्षण होगा। देश का हर नेता किसी न किसी के बारे में आए दिन जहर उगलता रहता है। अगर हर नेता की बात पर सुरक्षा बलों के जवान इसी तरह रिएक्ट करना शुरू कर दें तो देश की व्यवस्था का क्या होगा? क्या इसको बढ़ावा देना उचित है? क्या कल को और कोई नहीं ऐसे किसी नेता या पब्लिक फिगर पर हाथ उठेगा? क्या गारंटी है कि कल को यही घूम कर सभी के पास आएगा। थप्पड़ मारने को उचित नहीं कहा जा सकता, साथ ही ऐसे गुस्से को भी सुनना तो पड़ेगा, सुनना चाहिए।

राजनेताओं को समझना चाहिए कि पीड़ित जनता की भावनाओं के प्रति यदि वे न केवल संवेदनहीन बल्कि क्रूर व अमानवीय रवैया अपनाएंगे तो जनता अपनी हताशा किसी रूप में तो व्यक्त करेगी। किसी को थप्पड़ मारना अपराध है। इस तरह के मामलों में पुलिस आईपीसी के सेक्शन 323 के तहत केस दर्ज करती है। उन्होंने आगे कहा कि आईपीसी के सेक्शन 323 के तहत अगर कोई अपनी इच्छा से किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा करने पर उसे 1 साल की जेल हो सकती है। साथ ही 1 हजार रु पये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है, लेकिन अगर ये बात सामने आती है कि किसी ने बदसलूकी की और फिर ये घटना हुई तो अदालत सजा को बदल भी सकती है या मामले को ही खारिज कर सकती है। देश का हर नेता किसी न किसी के बारे में आए दिन जहर उगलता रहता है। अगर हर नेता की बात पर सुरक्षा बलों के जवान इसी तरह रिएक्ट करना शुरू कर दें तो देश की व्यवस्था का क्या होगा? अपनी ड्यूटी निभाते हुए यह करना क्या उचित है? इस प्रकार का अतिवाद ही आतंकवाद के लिए जगह बनाता है। एक बार फिर से इस राज्य में जिस तरह अलगाववाद फन फैला रहा है वो कभी भी पंजाब को उसके खूनी दौर में वापस पहुंचा सकता है।

(ये लेखक के विचार हैं)

गहराता जा रहा है संदेह

ऐसा पहली बार हुआ कि नीट-यूजी परीक्षा में बैठे 67 छात्रों ने पूरे अंक पा कर पहली रैंक हासिल की। ऑल इंडिया स्तर पर प्रथम रैंक अब तक एक या दो छात्रों को ही मिलती रही है। इसलिए संदेह गहरा गया है। यह संदेह गहराता जा रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाएं धांधली का जरिया बन गई हैं और यह सब कुछ प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। अनेक राज्यों में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं से यह शक बनना शुरू हुआ। अब देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट-यूजी) को लेकर खड़े हुए विवाद से यह और गहरा गया है। परीक्षा आयोजित कराने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) सवालों के घेरे में है। शक को इससे भी बल मिला कि जिस रोज लोकसभा चुनाव की मतगणना में सारे देश का ध्यान था, एनटीए ने उसी रोज इम्तहान के नतीजों को जारी करने का फैसला किया। ऐसा पहली बार हुआ कि इस परीक्षा में बैठे 67 छात्रों ने पूरे अंक पा कर पहली रैंक हासिल की। ऑल इंडिया स्तर पर प्रथम रैंक अब तक एक या दो छात्रों को ही मिलती रही है।

एनटीए ने सफाई दी है कि आसान परीक्षा, रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी, दो सही उत्तरों वाला एक प्रश्न और परीक्षा के समय में नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिया जाना ऐसे कारण हैं, जिनसे छात्रों को उच्च अंक लाने में सहायता मिली। मगर परीक्षा में शामिल हुए छात्रों के एक बड़े हिस्से को यह स्पष्टीकरण मंजूर नहीं है। वे परीक्षा रद्द कर इसे दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। एनटीए का कहना है कि 1,500 से ज्यादा उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क की समीक्षा करने के लिए चार सदस्यों की कमेटी गठित की गई है, जो एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मगर संदेह इतना गहरा है कि ऐसे स्पष्टीकरण से छात्रों एवं समाज के एक बड़े हिस्से को संतुष्ट करने में सफलता नहीं मिली है। आरोप है कि पेपर लीक किया गया। यह मुद्दा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से संबंधित जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने उठाया। उसने मामले की सीबीआई जांच और दोबारा परीक्षा कराने को कहा है। जो हालात हैं, उनके बीच इन मांगों को ठुकराना मुश्किल मालूम पड़ता है। अगर ऐसा कर भी दिया गया, तो यह परीक्षा की शुचिता पर संदेह जारी रखने की कीमत पर ही होगा।

इस चुनाव में आधी आबादी का हासिल

मनीषा प्रियम, राजनीतिक विश्लेषक

लोकसभा में इस बार महिलाओं का कुछ कम प्रतिनिधित्व होगा, मगर अब संभ्रांत घर की महिलाएं ही नहीं, दबी-कुचली जातियों की औरतें भी लड़कर इसमें आने को आतुर हैं। सतरहवीं लोकसभा का वह आखिरी सत्र था और विशेष भी, क्योंकि उसमें 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को पारित किया गया। इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि आने वाले वर्षों में (साल 2029 के आम चुनाव से संभवत:) लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। आरक्षण की यह सीमा 33 फीसदी तय की गई और इसे देश भर की विधानसभाओं पर भी लागू किया गया है। स्वाभाविक ही यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राजग सरकार की महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत था।

यूं तो महिला आरक्षण की चर्चा बतौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सन् 1989 में ही उठाई थी। तब केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था, जिसने ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रस्तावित किया। हालांकि, उनका वह विधेयक लोकसभा में तो पास हो गया, मगर राज्यसभा में गिर गया। उस वक्त खासकर सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले नेताओं ने ही इसका विरोध किया था। तब शरद यादव ने कुछ ऐसी टिप्पणी की थी, जिससे प्रतीत हुआ कि 'परकटी' महिलाएं वास्तव में जाति आधारित आरक्षण को महिला आरक्षण के परोक्ष प्रयोग से कमजोर बना देंगी। हालांकि बाद में, पीवी नरसिंह राव वाली कांग्रेस सरकार ने इसे पास किया। बावजूद इसके संसद में महिला आरक्षण की फाइल धूल-धूसरित ही रही। कहा यह भी जाता रहा कि बीजद या तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां बगैर आरक्षण के भी औरतों को खुले दिल से टिकट देती हैं, जिसका अर्थ है कि बगैर आरक्षण के उन्हें संसद में लाया जा सकता है।

इसी पृष्ठभूमि में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए। इसमें महिलाओं के बारे में दो बातें प्रमुखता से पूछी जा रही हैं। पहली, किस पार्टी ने कितने टिकट आधी आबादी को दिए और दूसरी, कहां से व कितनी औरतें चुनाव जीतने में सफल हुईं? हालांकि, चुनावी चर्चा में यह मुद्दा भी गरम रहा कि क्या महिलाएं सिर्फ एक वोट बैंक हैं और राष्ट्रीय चुनाव में क्या वे एकमुश्त नरेंद्र मोदी को अपना वोट देंगी? ऐसा इसलिए, क्योंकि अयोध्या में रामलला की मूर्ति-स्थापना के बाद माना जा रहा था कि महिलाएं इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगी और अपना वोट भाजपा को देंगी। मगर चुनाव-बाद की तस्वीर कुछ अलग दिख रही है। बेशक 'मोदी 3.0' एक मिली-जुली सरकार है, फिर भी रविवार को जब मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई गई, तो 72 माननीयों में केवल चार महिलाओं को यह सौभाग्य मिला। वैसे, लोकसभा में भी इस बार पिछली बार की तुलना में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व होगा। एडीआर के मुताबिक, 18वीं लोकसभा के लिए 74 महिलाओं का निर्वाचन हुआ है, जो कुल सांसदों का 13.6 प्रतिशत है। 17वीं लोकसभा में यह आंकड़ा 14 प्रतिशत था और 77 महिलाएं निचले सदन में आई थीं। हालांकि, 2014 के आम चुनाव में 542 में से 62 (11 प्रतिशत) महिला सांसद थीं, जबकि 2009 में 11 फीसदी (543 में से 59 सांसद) हिस्सेदारी आधी आबादी को हासिल हुई थी।

यदि विजेता उम्मीदवारों का लिंग के आधार पर विश्लेषण करें, तो इस बार बड़ी पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस सभी दलों पर भारी साबित होती दिख रही है। उसके 29 सांसदों में से 11 महिलाएं (38 प्रतिशत) हैं। इनमें कृष्णानगर से जीतने वाली महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं, जिनको कुछ ही महीने पहले लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस चूंकि 'इंडिया' ब्लॉक की प्रमुख सहयोगी है, इसलिए मुमकिन है कि विपक्ष में महिलाओं की आवाज बुलंद होती रहेगी। वैसे, कांग्रेस से जीतने वाली महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत 13 है, जबकि सपा से 14 प्रतिशत। रही बात भाजपा की, तो उसके कुल सांसदों में विजेता महिलाओं की हिस्सेदारी 13 फीसदी है।

यहां कुछ सांसदों का नाम उल्लेखनीय है, विशेषकर राजस्थान की भरतपुर सीट से निर्वाचित संजना जाटव की, जिनकी जीत बताती है कि अब संभ्रांत घर की महिलाएं ही नहीं, दबी-कुचली जातियों की औरतें भी लड़कर लोकसभा में आने को आतुर हैं। एक लंबे अरसे तक औरतों की यह कहकर आलोचना की जाती रही कि किन्हीं कारणों से यदि पति चुनाव नहीं लड़ पाता, तो उसके रिक्त स्थान को भरने के लिए पत्नी मैदान में उतारी जाती है। मगर अब युवतियां खुद अपनी लड़ाई लड़कर वर्ग-जाति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसी तरह, कर्नाटक से प्रियंका जारकीहोली, बिहार से शांभवी चौधरी, उत्तर प्रदेश से इकरा हसन और प्रिया सरोज की चर्चा स्वाभाविक है, जो युवा महिला सांसदों में शुमार हैं। यहां सोफिया फिरदौस का उल्लेख भी आवश्यक है, जो वैसे तो ओडिशा की पहली मुस्लिम महिला विधायक बनी हैं, लेकिन आईआईएम की पढ़ाई करने के बाद उनका इस तरह राजनीति में उतरना बदलते समाज का एक महत्वपूर्ण संकेत है। सवाल है कि आने वाले दिनों में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ाया जाए? इसके लिए तो सबसे पहले सभी दलों को औरतों को अधिक टिकट देना होगा, साथ ही महिलाओं को खुद भी सदन में पक्ष व प्रतिपक्ष की मुखर आवाज बनकर उभरना होगा। जरूरत इस बात की है कि महिलाएं राजनीतिक सरोकार से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर एकजुटता दिखाएं। जहां कहीं भी महिला अधिकारों का हनन हो, वहां उनको दलीय राजनीति से ऊपर उठकर उस महिला की प्रतिष्ठा का समर्थन करना चाहिए। मणिपुर में पिछले दिनों औरतों के अधिकारों का जिस तरह हनन किया गया, उसका एकजुट होकर विरोध जरूरी था, पर ऐसा हो नहीं सका। लिहाजा, महिला सांसदों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कैसे आधी आबादी की प्रतिष्ठा बनी रहे और वह भारतीय लोकतंत्र में समान नागरिक बनकर अपनी लोकतांत्रिक भागीदारी निभा सके।

चूंकि 2029 से महिला आरक्षण के तहत चुनाव संभावित हैं, इसलिए जो संसदीय क्षेत्र औरतों के लिए चिह्नित होंगे, उसमें यदि पार्टियां केवल मजबूत नेताओं की पत्नी-बेटी अथवा बहू को टिकट देंगी, तो स्वायत्तता से महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा। लिहाजा, राजनीतिक दलों पर यह दबाव भी बनाना चाहिए कि वे उन महिलाओं पर भरोसा करें, जो अपने बूते लड़ने में सक्षम हैं। वैसे, ईमानदारी से टिकट वितरण ही काफी नहीं है। संसदीय प्रणाली का प्रशिक्षण भी नवनिर्वाचित महिला सांसदों को देना होगा, तभी वे संसद में अपनी बात दम-खम के साथ रख सकेंगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Sargam Musicals
Deals in All Kinds of Musical Instrument Sales & Repair
DURG:- Near Tarun Adlabs Station Road, Durg (C.G.) Durg, Ph. 2330588, 9826660688
RAIPUR:- Near Manju Mamta Reaustaurant, M.G. Road Raipur. Ph. 4013288, 9303876196

गंजेपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी
पहले बाद में
JITU'Z CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली बेंगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

iti Industrial Training Institute
रमन (प्रा.) आई.टी.आई.
Recognised by: NCVT & DGT NEW DELHI, GOVT. OF INDIA
COPA
कोपा
STENOGRAPHER (Hindi)
स्टेनोग्राफर (हिन्दी)
योग्यता 10वीं उत्तीर्ण
(एक वर्षीय पाठ्यक्रम) - प्रवेश प्रारंभ
प्रवेश लेने पर फीस में विशेष छूट
एवं फीस मासिक किस्तों में
शासन द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति योजना
Raman I.T.I. : बाबा दीप सिंह नगर (वैशालीनगर), भिलाई, जिला-दुर्ग, छ.ग.
Call : 0788-4033571, 7389471941, 0788-4903573 4903572, 7773027492

श्रीकंचनपथ
छत्तीसगढ़

इनकम TAX
ITR फाईल
बनवायें मात्र 500/- में
TDS, GST, TAX Expert
सम्पर्क- शेखर गुप्ता
9300755544
onlytds@gmail.com WWW.ONLYTDS.COM

साय सरकार के छह माह : सुशासन के ट्रैक पर विकास ने फिर पकड़ी रफ्तार

किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए हुए ऐतिहासिक फैसले

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन के ट्रैक पर छत्तीसगढ़ ने फिर से विकास की रफ्तार पकड़ ली है। बीते छह माह पर नजर डाले तो साय सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत कम समय में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष 2047 तक विकसित-छत्तीसगढ़ का निर्माण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि के लिए सुशासन की स्थापना की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अलग सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। यह विभाग कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए काम कर रहा है। सभी विभागों को सुशासन के लिए अधिक से अधिक आईटी का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2023, सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।

साय सरकार ने आवासहीन और जरूरतमंद 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, 13 लाख से अधिक किसानों को धान की बोनस राशि, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी, महतारी वंदन योजना में 70 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को हर माह एक-एक हजार रूपए देने जैसे अनेक निर्णयों पर क्रियान्वयन किया है। राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवाद उन्मूलन के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियद नेल्लानार योजना शुरू की गई है। महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, रामलला दर्शन योजना, उद्यम क्रांति योजना जैसी कई अभिनव योजनाओं की शुरूआत हुई है। लोकतंत्र सेनानियों (मीसा बंदियों) की सम्मान निधि फिर से शुरू कर दी गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 13 जून से सभी विभागों में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए समीक्षा बैठक लेने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जन कल्याणकारी कार्यक्रम का क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता रखें। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि आम नागरिकों की दिक्कतें दूर करने के लिए संवेदनशील होकर कार्य करें। लोकसभा निर्वाचन के बाद अब शासन की योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार तेजी से काम कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना जैसी अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन पर तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्व प्रशासन को भी मजबूत किया जा रहा है। भूमि संबंधी विवादों और दिक्कतों को दूर करने के लिए भू-नक्शों की जियो रिफ्रेंसिंग पर भी रणनीति तैयार कर ली गई है।

पांच शक्तिपीठों का होगा विकास

राज्य की 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। शक्तिपीठों के विकास के लिए चारधाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना शुरू की जाएगी। ग्रामीण घरों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना

राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू करते हुए बजट प्रावधान भी कर दिया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है।

अधोसंरचना और कनेक्टीविटी पर जोर

राज्य में सड़क, रेल और हवाई यातायात की सुविधाओं के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। बिलासपुर और जगदलपुर से नयी उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। जशपुर और बलरामपुर हवाई पट्टी के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान कर दिया गया है। अंबिकापुर और जगदलपुर हवाई अड्डों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

गरीबों के लिए मुफ्त राशन

छत्तीसगढ़ सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 05 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 34 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए भी बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है।

राजिम कुम्भ कल्प की पुनः शुरूआत

राज्य की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए राजिम मेले का आयोजन पुनः उसके व्यापक स्वरूप में राजिम कुंभ कल्प के रूप में शुरू कर दिया गया है। बस्तर में प्राचीन काल से चले आ रहे अनेक ऐतिहासिक मेलों को भी शासकीय संरक्षण और सहायता दी जा रही है।

रायपुर में आईटी हब बनाने का काम शुरू

रायपुर को आईटी हब बनाने का काम शुरू हो गया है। हाल ही में 2 आईटी कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है, उन्हें फर्नीस्ड बिल्डअप एरिया भी उपलब्ध करा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार नवा रायपुर को बेंगलुरू की तर्ज पर आईटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना

राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के दो बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर (सिम्स) में भवन के विस्तार और सुविधाओं के विकास का काम शुरू कर दिया गया है।

आईआईटी की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थान

राज्य में उच्च शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। आईआईटी की तर्ज पर राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन की स्थापना की जाएगी।

राज्य-राजधानी क्षेत्र का विकास

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास योजना की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास के लिए विस्तृत योजना बनाने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए बजट में पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए खनिज परिवहन हेतु ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई है। इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी।

आर्थिक सलाहकार परिषद

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने तथा देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

18 लाख आवास स्वीकृत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति दे दी। इसके लिए 12 हजार 168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

13 लाख किसानों को धान का बोनस

मोदी जी ने प्रदेश के किसानों को गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर राज्य के किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस, सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित कर इस गारंटी को भी पूरा किया है।

3100 रूपए में धान की खरीदी

साय सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने की गारंटी को पूरा करते हुए 32 हजार करोड़ रुपए के समर्थन मूल्य की राशि का तत्काल भुगतान किसानों को किया और फिर 12 जनवरी को 24 लाख 75 हजार किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की है। इस साल खरीफसीजन में राज्य में 145 लाख मीटिरक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है।

70 लाख महिलाओं का वंदन

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल उपस्थिति में 10 मार्च 2024 को हुआ। इस योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। योजना का लाभ 70 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। अब तक इस योजना की चार माह की राशि जारी की जा चुकी है। पिछली सरकार ने महिला स्व सहायता समूहों से रेडी टू ईट का काम छीन लिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब फिर से उन्हें यह काम सौंप दिया है।

श्री रामलला दर्शन योजना

छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को अयोध्या में विराजमान श्री रामलला के दर्शन हेतु निःशुल्क आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना संचालित की जा रही है। शासकीय व्यय में अब तक हजारों दर्शनार्थी श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजे जा चुके हैं।

तेन्दूपत्ता संग्रहण दर अब 5500 रुपए

राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। चालू तेंदूपत्ता सीजन से ही 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को योजना का लाभ मिल रहा है। संग्राहकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चरण पादुका योजना भी शुरू की जाएगी, उन्हें बोनस का लाभ भी दिया जाएगा।

भर्ती में युवाओं को पांच वर्ष की छूट

युवाओं की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2028 तक आयु सीमा में 05 वर्ष छूट का लाभ मिलेगा।

यूपीएससी की तर्ज पर होगी पीएससी

यूपीएससी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए यूपीएससी के पूर्व चेयरमेन श्री प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया गया है। पीएससी की घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ली मनेंद्रगढ़ में जिला अधिकरियों की समीक्षा बैठक, कहा-

लोगों के छोटे-छोटे कार्यों को अधिकारी दें प्राथमिकता

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं बीस सूत्रीय कार्यान्वयन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली।

स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में कहा कि जिला कलेक्टर प्रत्येक साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में विभागीय योजनाओं की नियमित समीक्षा करें। राजस्व अधिकारी नामांतरण सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा कर बरसात के पहले निराकरण की कार्यवाही करें। लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाएं, जिससे आमजन को लाभ हो। आमाखेरवा में जो भी कार्यालय बनने वाले हैं उनका जिला अधिकारी संयुक्त सर्वे कर जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजे। उन्होंने विभिन्न विभागों को अनुपूरक बजट में कार्य जोड़ने के लिए प्रस्ताव जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व अमला से कहा कि जिले में जहां भी सामुदायिक उपयोग के जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। उसको पहले सख्ती से रोके। उन्होंने जिले में जितने भी वन अधिकार पत्र के पट्टे बटने है। उनका निराकरण यथाशीघ्र करने के निर्देश दिये। स्वास्थ्य मंत्री ने चिरमिरी नगर निगम आयुक्त को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने नगर पंचायत लेदरी, खोंगापानी, मनेंद्रगढ़ तथा झगराखाड़ में पानी एवं बरसात से पहले छोटे मोटे नालों की साफ-सफाई करने के लिए पीएचई, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग तथा एसईसीएल के अधिकारियों की संयुक्त बैठक कर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने सहकारिता एवं कृषि विभाग को संयुक्त रूप जिले में खाद एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने किसानों कम मात्रा में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में मिलेट बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। मिलेट्स के तहत कोदो- कुटकी, रागी, ज्वार, दलहन, तिलहन आदि फसलों के रकबा को बढ़ाने के निर्देश दिए तथा किसानों को प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को समय पर मानक बीज, खाद, कीटनाशक दवाई आदि वितरण सुनिश्चित हो। श्री जायसवाल ने जल संसाधन विभाग को साजाखाड़, सलका, अंजनी जलाशय, सिंघत, बरदर जलाशय के नहर लाइन को ठीक करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले में आय, जाति, निवास, आधार, आयुष्मान कार्ड के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में माह में एक-एक शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा की दीर्घकालीन रूप से आप जो भी कार्य करें उसे अच्छे से करें। लोगों के छोटे-छोटे कार्यों को प्राथमिकता से करें। जिलाधिकारी ऐसे लोगों के लिए प्रत्येक ब्लॉक में कैम्प लगाकर उनके कार्यों को कराना सुनिश्चित करें। इसी तरह उन्होंने लोक निर्माण विभाग, खनिज, श्रम, उद्योग, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पंचायत सहित विभिन्न शासकीय विभागों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

Since 1972
CROWN® - TV
Choice Of Millions
LED Available 16 -20 -22 - 24 - 32-40-50-55-65

Premier sales
8959493000
A Leela Electronics
9425507772
Reena Electronics
9329132299
Shree Electronics
7000827361
CONTACT
Maa Durga Electronics
9827183839
Rohit Electronics
94242-02866
Authorised Distributers For Chhattisgarh
Trade Enquiry: 98262-52372

खास खबर...

आज से रोज लगातार विभागों की समीक्षा बैठकें

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में विकास कार्यों की रफ्तार और तेज करने के लिए विभिन्न विभागों में चल रहे कामकाज की गहन समीक्षा शुरू कर दी है। आज से वे लगातार एक के बाद एक महत्वपूर्ण विभागों की बैठकें लेंगे और शासन की प्राथमिकताओं वाले कार्यों के संबंध में दिशा-निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा बैठकों की शुरूआत 13 जून को कृषि एवं उद्यानिकी तथा पशुधन विकास, मत्स्य पालन, दुग्ध महासंघ जैसे विभागों एवं संगठनों की समीक्षा के साथ की जाएगी। राज्य में शीघ्र ही मानसून के सक्रिय होने की संभावना है, इसे देखते हुए खेती-किसानी के काम में तेजी आ चुकी है। श्री साय किसानों को पहले ही आश्वस्त कर चुके हैं कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण खाद एवं बीजों की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा उद्यानिकी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह पशुधन विकास और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पहचान देश के प्रमुख मछली उत्पादक राज्य के रूप में होती है। राज्य सरकार मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकी है।

14 जून को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि प्रशासन की समीक्षा बैठकें लेंगे। इन बैठकों में वर्षा काल में होने वाली बीमारियों की रोकथाम की तैयारियों एवं दवाइयों की उपलब्धता के संबंध में वे जानकारी देंगे एवं आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। 15 जून को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, गृह एवं जेल विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। वर्षा काल में दूरदराज के क्षेत्रों में भी पीने के साफ पानी की उपलब्धता के संबंध में वे तैयारियों की समीक्षा करेंगे और आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। इसी तरह गृह एवं जेल विभाग की बैठक में वे राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे।

बालश्रम की रोकथाम हम सबकी जिम्मेदारीः मुख्यमंत्री

रायपुर (ए.)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय बालश्रम निषेध दिवस पर जारी अपने संदेश में कहा है कि बच्चे देश का सुनहरे भविष्य एवं समाज की अमूल्य निधि हैं, जिनका सरंक्षण और संवर्धन हम सबकी जिम्मेदारी है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर हम भविष्य की आशाओं और आकांक्षाओं का आधार बच्चों को बालश्रम के बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बच्चों की उचित देखभाल, पोषण, सुरक्षा, खुशहाल जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आगे बढ़ने के अवसर पर बच्चों का भी समान अधिकार है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि छोटे बच्चों को काम में न लगाएं, न ही किसी को लगाने दें।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना से रायपुर शहर में चलेंगी 100 इलेक्ट्रिक सिटी बसें

कलेक्टर गौरव सिंह ने किया आमानाका ई-बस डिपो का निरीक्षण

रायपुर (ए.)। राजधानी रायपुर की जनता को जल्द ही ई बसों से शहर में आने जाने की सुविधा मिलने वाली है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर को एक सौ नई बसें मिलेंगी। इन बसों के लगातार संचालन के लिए शहर के आमानाका और पंडरी में दो नए बस डिपो स्थापित किए जा रहे हैं। इससे रायपुर शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट सुविधा और भी आसान होगी। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने आज आमानाका में स्थापित होने वाले बस डिपो का निरीक्षण किया और वहाँ की जा रही तैयारियों- निर्माण कार्यों का जायज़ा लिया। उन्होंने ई बसों की चार्जिंग के साथ मेंटेनेंस के लिए सभी ज़रूरी इंतज़ाम जल्द करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

ग़ौरतलब है कि रायपुर शहर को केंद्र सरकार की ओर से एक सौ नई ई-बसें मिलने वाली हैं। ये बसें बैट्री से चलेंगी ।डिपो स्थलों पर इन बसों की बैट्री चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी बनाने की तैयारी है। पंडरी और आमानाका में बनने वाले सिटी बस डिपो बसों के लिए सेंटर पॉइंट होंगे ।इन दोनों डिपो से ही शहर के अलग अलग स्थानों के लिए सिटी बसें चलेंगी ।

100 नई बसें मिलने और 2 नए सिटी बस डिपो बनने से लोग आसानी से अलग-अलग जगहों के लिए बस पकड़ सकेंगे। बाहर से आने वाले लोगों को भी रायपुर शहर में एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसानी होगी। ये सभी बसें केंद्र सरकार की ओर से रायपुर सिटी को मिल रही हैं। नए डिपो बनाने की तैयारी रायपुर नगर निगम ने शुरू कर दी है। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आज आईएसबीटी का भी निरीक्षण किया। इसमें 1 एकड़ जगह को सिटी बस के स्टैंड के लिए फाइनल किया गया है। यहां पर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को शहर के भीतर किसी भी स्थान में जाने के लिए आसानी से सिटी बसें मिल जाएगी।

कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने बताया कि इस नए बस डिपो को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जाएगा। जिसमें बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वेटिंग एरिया और अन्य व्यवस्थाएं होंगी। निरीक्षण के दौरान रायपुर नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

निगम चुनाव से पहले होगा वार्ड परिसीमन

सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र किया जारी

रायपुर (ए.)। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आगामी नवम्बर-दिसम्बर में नगरीय निकायों में आम निर्वाचन के मद्देनजर सभी नगरीय निकायों में वार्डों के नए सिरे से परिसीमन के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। उन्होंने परिसीमन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसकी कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि राज्य के नगरीय निकायों का आम निर्वाचन इस वर्ष 2024 के नवम्बर-दिसम्बर माह में होना है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम-1961 के अनुसार नगरीय निकायों में वार्डों की रचना इस प्रकार से की जानी है कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या पूरे निकाय क्षेत्र में यथासाध्य एक जैसी हो तथा वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र संहत क्षेत्र हो। जनगणना निदेशालय द्वारा जनगणना-2011 के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन किया जा चुका है। प्रत्येक वार्डो की जनसंख्या में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए नए सिरे से वार्डों का परिसीमन किया जाना आवश्यक हो गया है। विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश का जिक्र करते हुए कलेक्टरों को नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन की कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने कहा गया है, ताकि समय-सीमा में मतदाता सूची आदि तैयार कराकर आम चुनाव नियत समयावधि में सम्पन्न कराया जा सके।

राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को अपने-अपने जिले में स्थित निकायों के वार्डों के परिसीमन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ नगर पालिका (वार्डो का विस्तार) नियम-1994 के अनुसार यथाशीघ्र पूर्ण कर प्रस्ताव विभाग को प्रेषित करने को कहा है, ताकि अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ के राजपत्र में कराया जा सके। परिसीमन संबंधी प्रस्ताव में प्रस्तावित वार्डों की चारों दिशाओं की सीमा तथा मानचित्र जिसमें प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की चारों दिशाओं को इस प्रकार दर्शाया जाए जिससे कि प्रत्येक वार्ड की सीमाएं स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिखे, को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रस्ताव में जनसंख्या संबंधी पत्रक जिसमें गत जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या, राज्य सरकार द्वारा संबंधित नगर पालिका क्षेत्र के लिए अवधारित वार्डों की कुल संख्या तथा इसके आधार पर प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या तथा प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़ों को भी शामिल करने को कहा गया है। प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या, प्रत्येक वार्ड से सम्मिलित क्षेत्र, हिन्दी व अंग्रेजी में अंतिम अधिसूचना का प्रारूप, वार्ड की उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम सीमा, वार्ड का क्रमांक तथा नाम, गत जनगणना में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार निकाय क्षेत्र की जनंसख्या संबंधी पत्रक जिसमें कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या, प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े, वार्डो की सीमा निर्धारण संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन, परिसीमन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों व सुझावों का निराकरण तथा वार्ड विभाजन संबंधी अंतिम अधिसूचना के प्रारूप का भी समावेश परिसीमन संबंधी प्रस्ताव में करने के निर्देश दिए गए हैं।

सीजी जीएसटी विभाग ने लॉन्च किया 'ई-संवीक्षा' पोर्टल

रायपुर (ए.)। छत्तीसगढ़ राज्य कर (जीएसटी) विभाग ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नई पहल करते हुए ई-संवीक्षा पोर्टल लॉंच किया है। यह पोर्टल रजत बंसल, आयुक्त, राज्य कर, छत्तीसगढ़ की पहल पर राज्य कर मुख्यालय, नवा रायपुर के डायरी कक्ष एवं कम्प्यूटर कक्ष द्वारा तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत मैदानी कार्यालयों के समुचित अधिकारियों द्वारा जीएसटी अधिनियम की धारा 61 एवं धारा 73 और/ अथवा धारा 74 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग आनलाईन की जानी है।

प्रारंभिक चरण में ई-संवीक्षा के अंतर्गत स्क्रूटनी माड्यूल बनकर तैयार है एवं लाईव किया जा चुका है तथा एड्जुडिकेशन माड्यूल तैयार किया जा रहा है। इससे न केवल विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मानिटरिंग की जा सकेगी बल्कि ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक डायरी भी आनलाईन होगी और एनालीटिक्स में इससे प्राप्त होने वाले आँकड़ों का राजस्व हित में उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के व्यापारियों को होने वाली व्यवहारिक परेशानियों का निराकरण करने मे भी ई-संवीक्षा माड्यूल कारगर साबित होगा।

गौरतलब है कि, राज्य कर आयुक्त के ध्यान में कुछ ऐसे प्रकरण आये थे जिनमें एक ही व्यवसायी की एक ही अवधि के प्रकरण में एक से अधिक अधिकारियों द्वारा अलग-अलग समय पर नोटिस जारी किए गये थे, जिसके बाद आयुक्त द्वारा ई-संवीक्षा माड्यूल की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू करवाया गया है।

जीएसटी और ई-वे बिल पर दिए सुझाव

कैट प्रतिनिधिमंडल ने की वित्तमंत्री से मुलाकात

रायपुर (ए.)। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जीएसटी से संबंधित नोटिस और ई-वे बिल से संबंधित सुझावों का ज्ञापन सौंपा।

पारवानी-दोशी ने वित्त मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में जीएसटी विभाग से अधिकांश व्यापारियों को नोटिस मिल रही हैं, जो व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य के विपरीत है। इसके अलावा, इन नोटिसों के कारण व्यापारी और उनके सलाहकारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय जीएसटी द्वारा मात्र 10 से 15 प्रतिशत व्यापारियों को नोटिस दिया जा रहा है, जबकि इनकम टैक्स विभाग के अंतर्गत केवल 5 प्रतिशत व्यापारियों को नोटिस मिल रही है। कैट ने सुझाव दिया कि इनकम टैक्स और केंद्रीय जीएसटी के समान केवल 10 से 15 प्रतिशत व्यापारियों को ही नोटिस दी जानी चाहिए।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में व्यापारियों को जीएसटीआर-1 फॉर्म देर से दाखिल करने पर जुर्माना नोटिस जारी किया गया है। विभाग की इस अचानक की गई कार्यवाही से व्यापारियों में भय का माहौल है और उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारिक समुदाय ने हमेशा सरकार को उसके कर संग्रह लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग दिया है और नियमों के पूर्ण अनुपालन के लिए प्रयासरत रहा है। इसलिए, जीएसटी विभाग द्वारा जारी किए गए जुर्माना नोटिस को स्वतः निरस्त किया जाना चाहिए।

ई-वे बिल अधिसूचना पर पुनर्विचार

कैट ने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि पूर्व में 19 जून 2018 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य में जिले के भीतर माल परिवहन के लिए ई-वे बिल जारी करना अनिवार्य नहीं था। 15 वस्तुओं को छोड़कर राज्य के भीतर किसी भी वस्तु के परिवहन पर ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान में जारी अधिसूचना क्रमांक 202 के कारण ई-वे बिल की संख्या और अनुपालन से संबंधित जटिलताएँ बढ़ जाएँगी। इसलिए, कैट ने आग्रह किया कि वर्तमान में जारी अधिसूचना पर पुनर्विचार कर पूर्व की अधिसूचना को यथावत रखा जाए।

वित्तमंत्री का सकारात्मक आश्वासन

ओ.पी. चौधरी ने ज्ञापन का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और इस विषय पर कैट प्रतिनिधिमंडल को सकारात्मक आश्वासन दिया कि व्यापारिक हितों का ध्यान रखा जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य

इस मुलाकात के दौरान कैट और युवा के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें जितेन्द्र दोषी, परमानन्द जैन, वासु माखीजा, सुरिन्द्र सिंह, भरत जैन, राकेश ओचवानी, जयराम कुकरेजा, प्रीतपाल सिंह बग्गा, सीए मुकेष मोटवानी, विक्रांत राठौर, परविन्द्र सिंह, अमीत गुप्ता और मनीष सोनी शामिल थे।

कलेक्टर-एसपी ने ली कानून व्यवस्था की बैठक

जमीनी स्तर पर मजबूत करें सूचना तंत्र, आपसी समन्वय सुदृढ़ होः कलेक्टर

रायपुर (ए.)। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह और एसपी संतोष सिंह ने आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित सभाकक्ष में कानून व्यवस्था की बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने पुलिस और प्रशासन को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने को कहा। ग्रामीण एवं शहरी सभी क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

कलेक्टर डॉ सिंह ने कहा कि मैदानी स्तर पर पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय होना जरूरी है। चाहे तहसीलदार हो या थाना प्रभारी हो अपने अपने क्षेत्र में ज़मीनी स्तर पर पहुँच बनाओ साथ ही कड़ाई से अपराधियों पर नकेल कसी जाए। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा किसी भी प्रकार की रैली या प्रदर्शन पर बराबर नज़र रखी जाए। दिन और रात में पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी हर क्षेत्र में नजर आनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस अमला संजीदगी से कार्य करे, हरेक घटना पर बारीकी से नजर रखें,घटना पर सावधानी पूर्वक और त्वरित कार्रवाई किया जाए । ला एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और समाज में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित हो सके।

एसएसपी संतोष सिंह ने कहा कि प्रशासन और पुलिस को एकजुटता से कार्य करना होगा। जिले में अपराधियों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई होनी चाहिए, विशेषकर क्राईसेस और लॉ एंड आर्डर के समय प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। अधिकारियों के व्यक्तिगत संबंध जनता से अच्छे होने चाहिए। इस तरह बेहतर समन्वय से लॉ एंड ऑर्डर स्थापित होगा।सूचना तंत्र मजबूत रखे,मैदानी अमला रूटीन के काम में एक दूसरे का सहयोग करे।

ज़िला पंचायत सीईओ विश्वदीप ने कहा कि पंचायती क्षेत्रों में सरपंच, सचिव, कोटवार और रोज़गार सहायक स्तर पर नाम नंबर सहित जानकारी राजस्व एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों-कर्मचारियों के पास उपलब्ध रहें जिससे आवश्यकता पड़ने पर त्वरित रूप से संपर्क साधा जा सके। इस अवसर पर अपर कलेक्टर कीर्तिमान राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर सहित पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

श्रमिकों के बुढ़ापे की चिंता हुई दूर, श्रममंत्री के निर्देश पर पेंशन जारी

रायपुर (ए.)। मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष पूर्ण कर चुके आठ और श्रमिकों के पेंशन को श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने निर्देश पर जारी किए गए। श्रमिकों के हित और उनके बेहतर जीवन यापन के लिए छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिकों के पेंशन योजना की शुरूआत 29 मार्च को की गई थी। इस योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को पेंशन राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा रही है। इसके अलावा भी कई सारे लाभ मिलेंगे। बुधवार को श्रम मंत्री और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष लखन लाल देवांगन ने आठ और श्रमिकों का पेंशन जारी किया।

इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव सरकार श्रमिकों की हितेषी है। सरकार की पूरी मंशा है की श्रमिकों को योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। श्रमिकों के हित एवं उनके बेहतर जीवन यापन के लिए निर्माण श्रमिकों के पेंशन योजना का लाभ श्रमिको को दिया जा रहा है। जिसमें पात्र निर्माण श्रमिकों को पेंशन राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। इस योजना के तहत् ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 साल पूरी चुकी है, उन श्रमिकों को हर महीने 1500 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। अगर पेंशनधारी निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो निर्माण श्रमिक के आश्रित (पति/पत्नी) को 750 रूपए मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इन जिलों के श्रमिकों को राशि हुई जारी महासमुंद के 2 श्रमिक, बेमेतरा के 4 श्रमिकों को, राजनांदगांव और दुर्ग के एक-एक श्रमिक को पेंशन जारी किया गया है।

लक्ष्मी जनरल एण्ड फैन्सी स्टोर्स
शहनाज, लोटस, हिमालया, Nature, Biotique, Bio Care
अरोमा, Good Vibes, Wow
ऑल ब्यूटी कॉस्मेटिक के थोक एवं चिल्हर विक्रेता
विशेष :- ब्यूटी पार्लर के सभी तरह की मशीने उपलब्ध है
Ajay Malghany 7389440364
Ramesh Maighany 9302457395
सर्कुलर मार्केट, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई

J.K. TRADERS
Mohit Ahuja:- 97550 01136, 98939 77337
PLASTO प्लास्टो है तो गॅरन्टी है।
Nandini Road, Power House, Distt.-Durg, Bhilai (CG)

आरना इंटरप्राईजेस
कांटावाला
वाटर प्यूरी फायर के विक्रेता एवं सुधारक
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त
इलेक्ट्रानिक तराजू एवं सीसीटीवी कैमरा के विक्रेता व सुधारक
सर्कुलर मार्केट केम्प-2, भिलाई, न्यू जेपी स्पोर्ट्स के सामने
7828844440, 9993045122
नया बस स्टैण्ड, शिव मंदिर रोड, दुर्ग, 09981370285, 9302833333

आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
अनुप ट्रेडर्स
सर्कुलर मार्केट, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई

प्रमोद इंटरप्राइजेस
गेंहू, चांवल एवं दाल के थोक विक्रेता
लिंग रोड, केम्प-2, भिलाई-दुर्ग
फोनः 0788-2225449, 93290-13017

● जीन्स
● टी-शर्ट
● शर्ट
● ट्राउजर
भारत जींस
जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई

BIHAR BOOT HOUSE
Jawahar Market, Power House
Bhilai 9826181183

जननी-एआई की कहानी में रोबोट की तरह एक्ट करना चैलेंजिंग था: आशिका भाटिया

टीवी की सबसे हाई प्रोफाइल एक्ट्रेस में से एक आशिका भाटिया जननी-एआई की कहानी शो में नजर आएंगी। उन्होंने अपने किरदार के बारे में बताया कि उनके लिए एआई रोबोट की तरह एक्ट करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। शो में आशिका चांदनी के रोल में नजर आएंगी।

आशिका ने कहा, मेरे किरदार का नाम चांदनी है। मैं एआई रोबोट हूं, जो इंसानों की तरह लगती है। मेरे लिए रोबोट का एक्ट करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। मैंने पहले कभी भी ऐसा रोल नहीं किया था, इसलिए मैं इस खास मौके का फायदा उठाना चाहती थी।

उन्होंने कहा, खास तौर पर चलते हुए किसी शो में आपको किसी ऐसे व्यक्ति की तरह बर्ताव करना होता है जो पहले से ही सीरीज में है। मेरे लिए किसी और की नकल करना काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया।

जननी-एआई की कहानी इरा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक वैज्ञानिक से मां बनी है। वह घातक बीमारी से अपनी बेटी की जान बचाने के लिए एआई रोबोट का आविष्कार करती है।

एमएजे प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित, जननी-एआई की कहानी दंगल टीवी पर प्रसारित हो रहा है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो आशिका को पिछली बार एंड टीवी पर वाणी रानी शो में देखा गया था। उन्होंने छोटे पर्दे पर मीरा शो में डेब्यू किया था। वह परवरिश - कुछ खट्टी कुछ मीठी में गुणवंत कौर अहलूवालिया के किरदार में नज़र आईं।

इसके अलावा, उन्होंने 2015 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान की छोटी बहन का किरदार भी निभाया।

आशिका ने लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स के रूप में एंट्री की, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद शो से बाहर आ गईं।

श्वेता तिवारी ने 43 की उम्र में फैंस के बीच शेयर किया समर लुक

एक्ट्रेस श्वेता तिवारी आए दिन अपनी बोल्ड तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर फैंस का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। उनकी हर एक फोटोज सोशल मीडिया पर आते ही बवाल मचाने लगती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपने लेटेस्ट समर लुक में तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस बेहद ही सेक्सी और स्टनिंग नजर आ रही हैं।

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपनी लेटेस्ट समर लुक्स की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में उनका क्यूट लुक देखकर फैंस अपने होश खो बैठे हैं। एक्ट्रेस जब भी अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं तो फैंस उनकी तस्वीरों पर अक्सर दिल हार जाते हैं। हालांकि इन तस्वीरों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है।

श्वेता तिवारी ने अपनी इन फोटोज को क्लिक करवाते हुए कैमरे के सामने खूबसूरत अंदाज में स्माइल देते हुए पोज दिए हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फ्लोरल लुक में शॉर्ट ड्रेस पहनकर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपने आउटलुक को कंप्लीट किया है। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का समर लुक लोग उनके स्टाइल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

बता दें कि, श्वेता तिवारी ने 43 साल की उम्र में भी खुद को काफी मेंटेंन कर के रखा हुआ है। हालांकि श्वेता तिवारी के चाहने वाले उन्हें उनकी बेटी पलक की बहन बताते हैं। श्वेता तिवारी इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। उन्होंने खुद की तरह, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी मेनटेन किया हुआ है।

रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 3 का टीजर जारी 21 जून से जियो सिनेमा पर होगा प्रीमियर

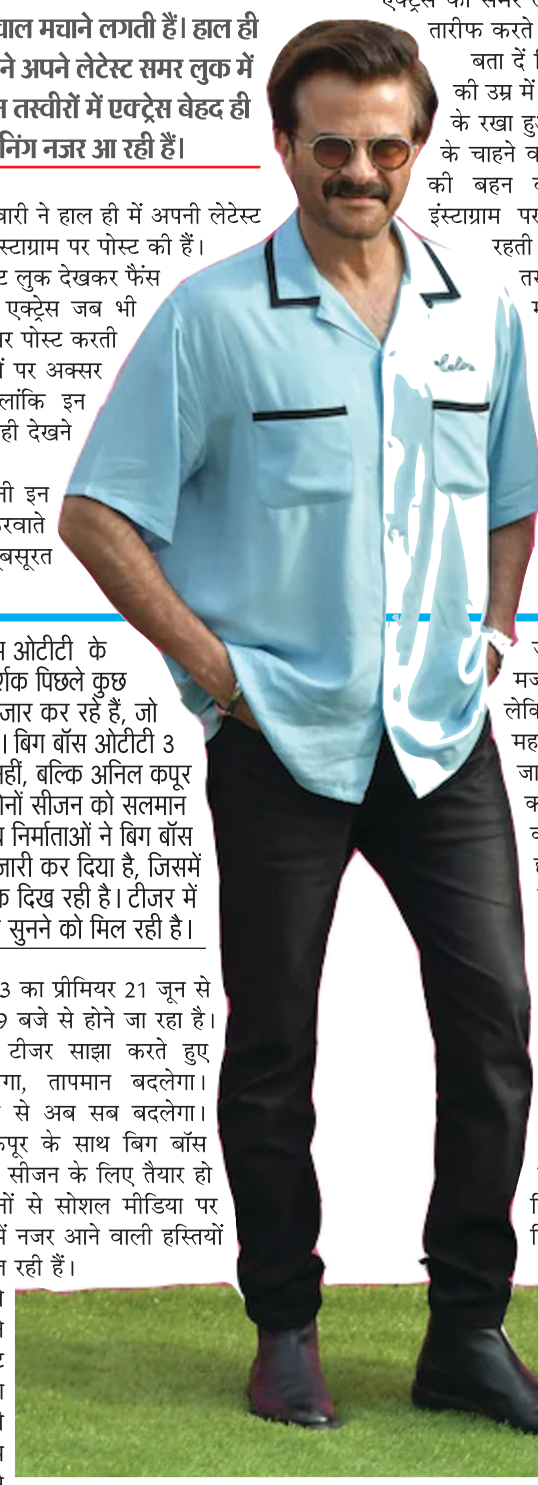

रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी के तीसरे सीजन का दर्शक पिछले कुछ समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द खत्म हो जाएगा। बिग बॉस ओटीटी 3 की मेजबानी सलमान नहीं, बल्कि अनिल कपूर करने वाले हैं। पहले दोनों सीजन को सलमान ने होस्ट किया था। अब निर्माताओं ने बिग बॉस ओटीटी-3 का टीजर जारी कर दिया है, जिसमें अनिल की झलक साफ दिख रही है। टीजर में उनकी दमदार आवाज सुनने को मिल रही है।

बिग बॉस ओटीटी 3 का प्रीमियर 21 जून से जियो सिनेमा पर रात 9 बजे से होने जा रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने टीजर साझा करते हुए लिखा, मौसम बदलेगा, तापमान बदलेगा। अनिल कपूर के आने से अब सब बदलेगा। हमारे होस्ट अनिल कपूर के साथ बिग बॉस ओटीटी 3के इस ख़ास सीजन के लिए तैयार हो जाइए।पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बिग बॉस ओटीटी 3 में नजर आने वाली हस्तियों को लेकर अटकलें चल रही हैं।

वहीं इस शो को लेकर अनिल कपूर ने भी अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए कहा कि, बिग बॉस ओटीटी और मैं एक ड्रीम टीम हैं. हम दोनों दिल से जवान हैं, लोग अक्सर कहते हैं मजाक में कि मैं रिवर्स एजिंग हूं, लेकिन बिग बॉस में ये खूबी है. ऐसा महसूस होता है जैसे स्कूल वापस जाना, कुछ नया और मजेदार ट्राई करना. मैं बिग बॉस में उसी एनर्जी को 10 गुना ज्यादा लाने जा रहा हूं. मैं इसमें अपना स्वाद लाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता.

इस शो में जाने वाले कई कंटेस्टेंट के नाम सामने आ रहे हैं. जिनमें रियाज़ अली, शिवांगी जोशी, शफक नाज़, दलजीत कौर, वायरल वडापाव गर्ल चंद्रिका, यूट्यूबर जैन सैफी, विक्की जैन और अदनान शेख शामिल हैं. इसके अलावा कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन त्रिशाला दत्त, अहाना देओल, मिथुन चक्रवर्ती के बेटे उष्मेय चक्रवर्ती और तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम भव्या गांधी के नाम को लेकर भी चर्चा चल रही हैं. हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

तीन अच्छे दोस्तों की दो प्रेमकहानियों के बीच उलझी है

रोहित सराफ की इश्क विश्क रिबाउंड का ट्रेलर जारी

कहते हैं, जब प्यार हो जाए तो सब में उसी का चेहरा दिखता है। इश्क विश्क रिबाउंड का ट्रेलर इसी एक लाइन शुरू होता है और दर्शकों पर अपनी अमिट छाप भी छोड़ देता है। इश्क विश्क रिबाउंड का पहला ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में पश्मीना रोशन, रोहित सराफ, नैला ग्रेवाल और जिबरान खान मुख्य भूमिका में हैं। यह 21 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्म का शीर्षक है, इश्क विश्क रिबाउंड, जिसमें रिबाउंड का मतलब है किसी मुश्किल ब्रेकअप के बाद किसी के साथ रिश्ता बनाना। ट्रेलर में दिखाया गया है कि पश्मीना रोशन और रोहित सराफ करीबी दोस्त हैं, जो अपने-अपने पार्टनर से अलग हो जाते हैं और बाद में उन्हें एहसास होता है कि वे सच में एक-दूसरे के प्रति आकर्षित हैं।

फिल्म का ट्रेलर साझा करते हुए मेकर्स ने लिखा, तीन सबसे अच्छे दोस्तों, 2 रिश्तों, 2 ब्रेकअप और सामने आने वाली उलझनों के सफर का अनुभव करें। देखें कि जब रोमांस की चिंगारी निकलती है तो रिश्ते कैसे बदलते हैं। आप यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या एक्स वाकई दोस्त बने रह सकते हैं? ऐसे दौर में जब लेबल कम मायने रखते हैं, इश्क विश्क रिबाउंड आप सब से पूछता है। रिश्ते को क्या परिभाषित करता है? रिश्ते को नाम देना जरूरी है क्या?

फैंस फिल्म के ट्रेलर को देख कर काफी उत्साहित हो गए हैं। एक यूजर ने लिखा, रोहित भाई की एक और धमाकेदार फिल्म। अब इसकी रिलीज का इंतजार है। दूसरे यूजर ने लिखा, रोहित और पश्मीना एक और हिट के लिए तैयार हैं। दोनों को ढेरों शुभकामनाएं। एक और यूजर ने लिखा, ट्रेलर तो गजब का है। अब बस फिल्म का इंतजार है। रमेश तौरानी और जया तौरानी द्वारा निर्देशित, इश्क विश्क रिबाउंड को निपुण अविनाश धर्माधिकारी ने निर्देशित किया है। यह 21 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

गर्मी के दिनों में पीएं ठंडा-ठंडा मौसंबी का जूस, मिलेंगे ये 5 मुख्य फायदे

मौसंबी का जूस गर्मी में जूस की दुकानों पर मिलने वाला सबसे लोकप्रिय पेय है। यह मौसंबी फल के खट्टे स्वाद और चीनी की मिठास का एक अद्भुत संयोजन होता है, जिसे पीने से ताजगी मिलती है।इस पेय में कई तरह के लाभ भी छिपे होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। इस जूस को अपनी डाइट में शामिल करने से आप शरीर को डिटॉक्सीफाई भी कर सकेंगे।आइए जानते हैं मौसंबी जूस के सेवन के फायदे।

वजन घटाने में मिलेगी मदद

मौसंबी का जूस एक कम कैलोरी वाला पेय है, जिसमें अच्छी मात्रा में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं। इस स्वादिष्ट जूस के सेवन से वजन घटाने में मदद मिलती है।अगर आप स्वस्थ खान-पान के जरिए अपना वजन कम करना चाहते हैं तो इसे आहार का हिस्सा बनाएं। मौसंबी के जूस का सेवन तृप्ति की भावना को बढ़ाने और भूख को रोकने में मदद कर सकता है।आप स्ट्रॉबेरी का जूस पीकर भी कई लाभ पा सकते हैं।

दिल का स्वास्थ्य होता है दुरुस्त

मौसंबी के जूस का नियमित सेवन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ ही इससे हृदय स्वास्थ्य को दुरुस्त करने में भी मदद मिल सकती है।मौसंबी के जूस में एंटीऑक्सिडेंट और पोषक तत्व होते हैं, जो रक्तचाप के स्तर और हृदय रोगों के लक्षणों को कम करते हैं। रोजाना एक गिलास मौसंबी का जूस पीने से आप स्ट्रोक और दिल के दौरे जैसी परेशानियों से भी बच सकते हैं।

शरीर होता है डिटॉक्सीफाई

मौसंबी का जूस भी शरीर को डिटॉक्स करने के लिए एक बेहतरीन पेय होता है। यह सुबह के वक्त पीने के लिए बिलकुल सही पेय है, जो हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बेअसर करने में मदद करता है।साथ ही इसके सेवन से तनाव भी कम किया जा सकता है। सुबह सबसे पहले मौसंबी का जूस पीने से मूड और ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

हाइड्रेशन

इस भीषण गर्मी के बीच धूप के कारण हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। इसके चलते चक्कर आना, बेहोशी आना और बेचैनी आने जैसी परेशानियां हो सकती हैं।मौसंबी के जूस में अच्छी मात्रा में पानी मौजूद होता है, जो शरीर को प्राकृतिक हाइड्रेशन प्रदान करता है। इस लजीज पेय को पीने से आपको निर्जलीकरण और गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचने में भी सहायता मिलेगी।आपको बेल का जूस पीने से भी कई लाभ मिल सकते हैं।

बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता

मौसंबी का जूस पीने से शरीर को अच्छी मात्रा में विटामिन- सी और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। इन तत्वों के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है।इसके अलावा, इस पेय में मौजूद फ्लेवोनोइड्स मुक्त कणों के कारण होने वाली सूजन को भी रोकते हैं। मौसंबी के जूस में मौजूद विटामिन सी बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमें स्वस्थ रखता है।वजन घटाने के लिए सब्जियों से बने जूस का सेवन करें।

खास खबर

नगर निगम भिलाई के सभी कार्यालयो में मनाया गया ड्राई डे

भिलाई। नगर निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय एवं सभी जोन कार्यालय में निर्धारित समय अनुसार दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में फाईट द बाईट मच्छर उन्मूलन के तहत जन जागरूकता अभियान अंतर्गत ड्राई डे मनाया गया। आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने सभी विभाग के अधिकारियो एवं कर्मचारियो को निर्देश दिये थे कि प्रत्येक बुधवार को निगम के सभी कार्यालय में ड्राई डे मनाया जायेगा। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी स्वयं सभी विभाग में जाकर कर्मचारियो को प्रेरित कर रहे थे सभी को प्रत्येक बुधवार को ड्राई डे मनाने के लिए कहा साथ ही उन्होने हिदायत दी की मैं आकस्मिक रूप से आकर कार्यालयीन अवधि में चेक करूगां। कहीं भी कुलर में मच्छर, लार्वा पाये जाने पर तथा चारो तरफ साफ-सफाई नहीं मिलेगी तो संबंधित के उपर कार्यवाही की जावेगी। सब को सर्तक रहना है अपने आफिस एवं घर को जलजनित एवं मच्छर जनित बिमारी से बचना है। फाईट द बाईट योजना की शत् प्रतिशत सफलता तभी मिलेगी जब सभी लोग जागरूक होगे। जल के माध्यम से उत्पन्न होने वाले जीवानु एवं किटानुओ को मारना। जिससे डेंगू, मेलेरिया, डायरिया, पीलिया इत्यादि बीमारी न हो।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 को

दुर्ग। जिले में 21 जून 2024 को दशम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग में प्रातः 6 बजे से 7 बजे के मध्य किया जाएगा। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु अधिकारियों को कार्य दायत्वि सौपे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अश्वनी कुमार देवांगन नोडल अधिकारी होंगे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग मुकेश रावटे को कानून व्यवस्था/संपूर्ण तैयारी/जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रोटोकॉल अधिकारी हरवंश सिंह मिरी को मुख्य अतिथि एवं जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण कार्ड वितरण, आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग श्री लोकेश चन्द्राकर को पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग की सफाई/गद्दे/टेन्ट/दरी/भौतिक व्यवस्था/विडियो/फोटो ग्राफी व्यवस्था/माईक व्यवस्था/शौचालय व्यवस्था, जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग अरविन्द मिश्रा को योग प्रशिक्षकों की उपस्थिति/शैक्षणिक संस्थानों/के सभी कर्मचारियों/छात्रों एवं स्काउट गाईड/एन.सी.सी./एन.एस.एस. के छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग एस.के. श्रीवास को आमंत्रण पत्र कार्ड प्रिंटिंग/मंच निर्माण/मंचीय बैनर व्यवस्था करना, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक दुर्ग हेमंत कुमार साहू को चिकित्सीय टीम एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए दायित्व सौपे हैं।

जन सहयोग से आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए मिले 20 कूलर

गरियाबंद। कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल के अपील पर जनसहयोग से महिला एवं बाल विकास विभाग को 20 कूलर समाज सेवको के द्वारा प्रदाय किया गया है। कलेक्टर अग्रवाल ने कलेक्टोरेट परिसर में प्राप्त कूलर को 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपा। इस दौरान कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राप्त कूलरों का व्यवस्थित रख-रखाव करते हुए, सुरक्षित रूप से उपयोग करने के निर्देश दिये। यह कूलर फिंगेश्वर, छुरा तथा गरियाबंद के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदाय किया गया है। उक्त कूलर उन्ही आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्रदान किया गया है, जहाँ पूर्व से विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है। कूलर प्रदान करने के दौरान संयुक्त कलेक्टर राकेश गोलछा, डीपीओ श्री अशोक पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि आंगनबाड़ी की सेवाएं वर्ष में 300 दिवस अनिवार्य रूप से देना होता है। जिसके फलस्वरूप भीषण गर्मी में भी आंगनबाड़ी केन्द्रों को शासन के द्वारा बंद नही किया जाता है। अत्यधिक गर्मी के कारण आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति प्रभावित होती है तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा देने में काफी कठिनाई होती है। कलेक्टर अग्रवाल के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए जनसहयोग से कूलर प्रदाय करने की अपील की थी। इसी तारतम्य में जन सहयोग से 20 कूलर आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्राप्त हुए।

ओडिशा में पहली बार भाजपा की सरकार

मोहन माझी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, पीएम मोदी रहे मौजूद

भुवनेश्वर(एजेंसी)। विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा ने ओडिशा में सरकार बनाई है। बुधवार को ओड़िशा में भाजपा की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। क्योंझर से विधायक मोहन चरण माझी ने ओडिशा में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसी के साथ ओडिशा में पहली बार एक सीएम, दो डिप्टी सीएम और 13 मंत्रियों की सरकार बनी।

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के जनता मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। बुधवार शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ। शपथ समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर पहुंचे। एयरपोर्ट पर ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास और स्वयं मोहन चरण मांझी ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल व पूर्व सीएम नवीन पटनायक भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

बता दें कि इस बार ओडिशा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में बीजू जनता दल के विजयरथ को रोका और बड़ी जीत दर्ज की। 147 में से 78 सीटों पर जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी ओडिशा में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी।

पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए बिना पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। उधर, बीजू जनता दल को 51 सीटों पर जीत हासिल हुई।

आदिवासी नेता मोहन माझी ने विधानसभा चुनाव में क्योंझर सीट से जीत हासिल की है। इस चुनाव में उन्होंने बीजू जनता दल की मीना माझी को 11,577 मतों से शिकस्त दी। 52 वर्षीय भाजपा नेता की विधानसभा चुनाव में यह चौथी जीत है। वह पहली बार 2000 में क्योंझर (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2004, 2019 और अब 2024 में भी क्योंझर सीट से जीते हैं। माझी ओडिशा विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक भी रह चुके हैं। चार बार एक ही विधानसभा से जीत दर्ज करने वाले मोहन माझी पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया और उन्हें ओडिशा का 15वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया है।

आयुक्त ने ली राजस्व विभाग की बैठक शतप्रतिशत वसूली का रखा लक्ष्य, बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता रहेगी

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। नगर निगम आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने राजस्व विभाग के अधिकारियो एवं कर्मचारियों की समीक्षा बैठक लेकर वार्डवार वसूली की जानकारी ली और गत सप्ताह बैठक में दिये गये निर्देश की जानकारी लेकर वित्तीय वर्ष पर शतप्रतिशत वसूली के निर्देश दिये।

आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने बैठक में समस्त सहायक राजस्व निरीक्षकों व राजस्व उप निरीक्षकों से उनके प्रभारित वार्डो की वार्डवार वसूली की जानकारी ली तथा गत सप्ताह के बैठक में दिये गये निर्देश की जानकारी लेकर राजस्व वसूली शत प्रतिशत वसूली के निर्देश दिये। प्रत्येक वार्ड प्रभारी घर घर जाकर वसूली करे, अवकाश के दिनों में आधा दिन भी घर घर वसूली करने के साथ साथ निगम के राजस्व कार्यालय में भी वसूली करना सुनिश्चित करे। इसके अलावा नामांतरण के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करे और भवन पूर्णता के आधार पर संपत्तिकर अधिरोपित करें। जिससे करों में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि जल विभाग से समांजस्य कर नये घरों से जलकर की वसूली करे।बैठक में सहायक राजस्व अधिकारी शुभम गोइर ने कहा कि बकाया राशि की वसूली करना हमारी प्राथमिकता रहेगी।आयुक्त ने कहा इसी प्रकार भवन शाखा से नये मकानों की जानकारी लेकर सम्पत्तिकर, जलकर व समेकितकर की वसूली करे।

जिससे शतप्रतिशत वसूली हो सके।आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने कहा कि सहायक राजस्व निरीक्षक एवं वार्ड प्रभारी जो करदाता जलकर सहित अन्य कर जमा नहीं कर रहे है ऐसी स्थिति में संबंधित का नल विच्छेदन की कार्यवाही करे। और उन्होंने करों का भुगतान नहीं किया है उनकी कुर्की की कार्यवाही करे।उन्होंने कहा कि लंबे समय से बकाया दुकानदारों की दुकाने को नोटिस जारी कर कार्यवाही करे। आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने सहायक राजस्व अधिकारी शुभम गोइर से कहा कि बड़े बकायादारों से कडाई से वसूलना सुनिश्चित करे तथा प्रतिदिन की वसूली की जानकारी लेवे।

नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर बनवा सकते है आयुष्मान कार्ड

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। केन्द्र सरकार की आयुष्मान कार्ड योजना कमजोर वर्गों को चिकित्सा सहायता और सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक पहल है। जिसके तहत शासन के निर्देशानुसार सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना (एसईसीसी)अंतर्गत परिवार एवं अंत्योदय व प्राथमिकता के क्रियाशील राशन कार्डधारी परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

योजनान्तर्गत शासकीय जिला चिकित्सालय रायगढ़ या किसी पंजीकृत चिकित्सालयों में योजना के निर्धारित चिकित्सा पैकेजों के माध्यम से भर्ती होने की स्थिति में प्रतिवर्ष (फैमिली फ्लोटर आधार पर)प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क इलाज प्रदाय किए जाने का प्रावधान है।

कलेक्टर श्री गोयल ने पूरे जिले में आयुष्मान कार्ड के काम को मिशन मोड में एक मुहिम के रूप करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सीएमएचओ से कहा कि अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले लोगों की स्क्रुटनी कर ऐसे लोगों की पहचान की जा सकती है जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं। जिससे वहीं उनके कार्ड बनाने की प्रक्रिया की जा सकती है। सीएमएचओ ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 12 जून 2024 तक की स्थिति में कुल 1087479 लक्ष्य में से 886773 (81.5 प्रतिशत)हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया जा चुका है। कलेक्टर गोयल ने शेष हितग्राहियों का शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु निर्देशित किया है। जिस पर सीएमएचओ ने बताया कि छूटे हुए हितग्राहियों की जनसंख्या का आंकलन करते हुए रूट चार्ट बनाकर शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड पंजीयन कराया जाना है। साथ ही हितग्राही स्वयं अपना आयुष्मान कार्ड ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीयन कर सकते है।

जिले के जनसामान्य राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोयुक्त अन्य कोई भी शासकीय पहचान पत्र एवं मोबाईल नंबर के साथ नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या शिविर में उपस्थित होकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी एवं किसी भी प्रकार की सहायता हेतु हेल्प लाईन नंबर 104 में संपर्क कर सकते है।

भिलाई में हजार स्क्वायर फीट से अधिक के मकानों में सीसीटीवी होगा अनिवार्य, विधायक रिकेश ने रखा प्रस्ताव

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। शहर में भवन पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए एक और शर्त अनिवार्य हो सकती है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने 1000 स्क्वायर फीट या उससे अधिक के मकानों में सीसी टीवी कैमरे अनिवार्य करने के संबंध में भिलाई निगम के महापौर नीरज पाल से चर्चा कर इसका प्रस्ताव सामान्य सभा में लाने कहा है। यदि भिलाई निगम की सामान्य सभा में यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो लोगों को अपने मकानों में सीसी टीवी कैमरे लगाना अनिवार्य हो जाएगा।

इस संबंध में विधायक रिकेश सेन ने कहना है कि एक हजार वर्गफीट और उससे बड़े भूखंड में जैसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को आवश्यक माना जाता है उसी तरह अब ऐसे निर्माणाधीन मकानों में सीसीटीवी लगाने के बाद ही मकान मालिकों को भवन पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विधायक रिकेश सेन का ने कहा कि घर बनाने के बाद जैसे लाखों रुपए इसके इंटीरियर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, माडुलर किचन, सीलिंगआदि में खर्च करते हैं, उसी तरह मात्र 5 से 10 हजार रुपए खर्च कर सीसीटीवी सेटअप भी लगवा सकते हैं। विधायक रिकेश का कहना है कि सीसीटीवी न केवल घर की सुरक्षा के मद्देनजर जरूरी है बल्कि वह चोरी या अन्य घटना दुर्घटना को रोकने में भी सहायक होता है। इसे देखते हुए निगम महापौर से चर्चा कर इस बावत प्रस्ताव सामान्य सभा में लाए जाने की बात कही है, ताकि लोग अपने घरों में आवश्यक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और सीसीटीवी सेटअप लगा कर निगम से भवन पूर्णता प्रमाण पत्र हासिल कर सकें।

विधायक रिकेश सेन ने वैशाली नगर विधानसभा के सभी नागरिकों, व्यावसायिक संस्थानों व व्यापारियों? और प्रायवेट कालोनीवासियों से भी अपील की है कि सीसीटीवी सिस्टम आप अपने स्टोर या बिल्डिंग के मुख्य क्षेत्रों में अवश्य लगाएं। सीसीटीवी कैमरे बिल्डिंग के कोनों में, प्रवेश द्वार और निकास द्वार के सामने और चेकआउट काउंटर के पीछे लगाया जा सकता है। खासकर कैमरों की स्थिति उन छवियों और कोणों को पर भी कार्य करती है जहां सामान्यतः हम सबकी नजर नहीं पड़ती है। सीसीटीवी सिस्टम सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाकर आपके व्यवसाय के स्वास्थ्य और लाभप्रदता में भी बहुत मदद करता है। विधायक रिकेश ने कहा कि शहर को सुरक्षित और संरक्षित रखने में सीसीटीवी का उपयोग विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों में परिधि सुरक्षा बनाए रखना, यातायात की निगरानी करना, खतरनाक स्थानों की निगरानी करना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इमारतों और सूने मकान की सुरक्षा को बनाए रखना शामिल है।

योजनाबद्ध तरीके से युद्धस्तर पर अभियान चलाकर किया जाएं पौधारोपण - कलेक्टर

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागृह में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से किसान वृक्ष मित्र योजना की जानकारी लेते हुए इसके अंतर्गत हो रही गतिविधियों पर चर्चा की।

किसान वृक्ष मित्र योजना का उद्देश्य कृषकों एवं अन्य हितग्राहियों के निजी भूमि पर वाणिज्यिक प्रजातियों के वृक्षों का रोपण कर सहयोगी संस्था एवं निजी कंपनियां के माध्यम से उत्पाद की वापस खरीदी करते हुए उनके आय में बढ़ोतरी करना है। समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय,

अर्ध शासकीय एवं शासन के स्वयत्त संस्थाएं जो अपनी स्वयं की भूमि पर रोपण करना चाहते है इनके आलावा निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायते, भूमि अनुबंध धारक जो अपनी भूमि में रोपण करना चाहते हैं इस योजना हेतु पात्र होंगे। योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि पर 5 हजार पौधे निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे एवं उनके रखरखाव हेतु जीवित प्रतिशत पौधों के आधार पर निर्धारित दर पर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार 5 एकड़ से अधिक भूमि होने पर प्रति एकड़ 1 हजार पौधे निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे एवं जीवित प्रतिशत पौधों के आधार पर 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। योजना में क्लोनल नीलगिरी, रूटशूट सागौन, टिश्यू कल्चर सागौन, चंदन, मिलिया डुबिया, सामान्य बांस, टिश्यू कल्चर बांस प्रजातियों के पौधे निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। वृक्ष परिपक्व होने के पश्चात् शासन द्वारा सहयोगी संस्था/निजी कंपनियों के माध्यम से निर्धारित समर्थन मूल्य पर वापस खरीदी का प्रावधान होगा। रोपण पश्चात् आगामी 2 वर्षों में जीवित पौधों की संख्या के आधार पर रखरखाव हेतु प्रति पौधा वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। जिसके अनुसार टिश्यु कल्चर बांस, टिश्यु कल्चर सागौन एवं मिलिया डुबिया प्रजाति के पौधों के लिए प्रथम वर्ष 10.50 रूपए, द्वितीय व तृतीय वर्ष 6.50-6.50 रूपए प्रति पौधा की दर से दिए जाएंगे। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन हेतु योजनाबद्ध तरीके से युद्धस्तर पर वृक्षारोपण करने एवं अधिक से अधिक कृषक लाभार्थियों को योजना में सम्मिलित करने हेतु बल देकर कार्य करने कहा।

जंगलों को आग से बचाने के लिए हुए व्यापक इंतजाम

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। वनों का अग्नि से बचाव अत्यंत आवश्यक है। इसके मद्देनजर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा प्रदेश के वन क्षेत्रों में आग से बचाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत 15 जून 2024 तक वनों को अग्नि से बचाव वन विभाग की प्राथमिकता में है।

वन विभाग द्वारा इसके अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय अरण्य भवन रायपुर में कन्ट्रोल रूम में टॉल फ्री नम्बर 18002337000 स्थापित किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति अग्नि घटनाओं की सूचना दे सकते हैं। इसी तरह समस्त वनमंडलों में भी वनमंडल कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से अग्नि घटनाओं की सतत् निगरानी की जा रही है।

वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अग्नि सीजन 15 फरवरी से प्रारंभ हो गया है तथा 15 जून 2024 तक वनों को अग्नि से बचाना विभाग की प्राथमिकता में है। अग्नि से जहां एक ओर प्राकृतिक पुनरूत्पादन के पौधे नष्ट हो जाते हैं वहीं दूसरी ओर वृक्षों की काष्ठ की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। अतएव वनों को अग्नि से बचाव अत्यंत आवश्यक है। अग्नि सुरक्षा हेतु समस्त वनमंडलों में अग्नि रेखाओं की कटाई, सफाई, जलाई की जा चुकी है। वन क्षेत्रों में अग्नि से सुरक्षा हेतु कैम्पा मद से समस्त बीटो में एक-एक अग्नि रक्षक की नियुक्ति की गई है।

कलेक्टर की पहल से वृद्धाश्रम एवं दिव्यांग बच्चों के विद्यालय को मिला विभागीय अनुदान

गरियाबंद। कलेक्टर दीपक अग्रवाल की पहल से जिले के वृद्धाश्रम एवं दिव्यांग बच्चों के विशेष विद्यालय को राज्य शासन की तरफ से विभागीय अनुदान की स्वीकृति मिली है। इनमें समाज कल्याण विभाग से विभागीय मान्यता प्राप्त संस्था प्रेरक स्वैच्छिक संस्था द्वारा संचालित सक्षम दिव्यांग विद्यालय राजिम एवं सियान सेवा सदन वृद्धाश्रम आश्रम ग्राम-भिलाई शामिल है। शासन से अनुदान की स्वीकृति मिलने से आश्रम में निवासरत वृद्धजनों एवं दिव्यांग स्कूल के बच्चों को विशेष सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही दिनचर्या के कार्यों में उपयोगी सामग्रियों की भी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

खास खबर

धान कारोबारी को बंधक बनाकर लूटा, दफ्तर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम

रायपुर। राजधानी रायपुर में बुधवार को लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। खरोरा थाना क्षेत्र में एक धान कारोबारी को उसी के दफ्तर में बंधक बनाकर लूट लिया गया। दिनदहाड़े दफ्तर में घुसे बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर पहले उसे बंधक बनाया और उसके बाद रुपयों से भरा बैग लेकर भाग निकले। सूचना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर दी। आसपास के सीसी टीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार लूट की यह वारदात तिल्दा निवासी व्यापारी विष्णु शर्मा के साथ हुई है। वे किसानों और राइस मिलर्स के बीच धान की खरीदी-बिक्री करने का काम करते हैं। बुधवर की सुबह करीब 11 बजे जैसे ही अपने खरौरा स्थित दफ्तर पहुंचे थे दो नकाबपोश बदमाश उनके ऑफिस में घुसे और पिस्टल निकाल कर उनपर तान दी। इसके बाद बदमाशों ने व्यापारी को अंदर कमरे में बंद कर दिया और उसके रुपए भरा बैग लेकर भाग गए। इसके कुछ देर बाद व्यापारी किसी तरह कमरे से बाहर निकला और पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकेबंदी शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसी टीवी फुटेज खंगाल रही है।

घर के सामने टहल रही प्रोफेसर चैन स्नैचिंग की हुई शिकार

भिलाई। खाना खाकर बेटे के साथ रात में घर के बाहर टहल रहीं शासकीय महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर के गले से सोने की चैन खिंच बाईक सवार निकल भागा है। घटना भिलाई के नेवई थानांतर्गत मैत्री कुंज क्षेत्र में कल रात लगभग 9 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात बाईक चालक के खिलाफ धारा 356 और 379 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

नेवई थाना प्रभारी ने बताया कि निकुम शासकीय महाविद्यालय में असिटेंट प्रोफेसर श्रीमती अन्नपूर्णा यादव (40 वर्ष)कल रात्रि में खाना खाकर अपने बेटे प्रत्युश के साथ मैत्री कुंज की स्ट्रीट 10 स्थित अपने घर के बाहर टहल रही थीं। घर के सामने रात्रि करीब 9 बजे एक अज्ञात बाईक सवार हेलमेट पहनकर पीछे से आया और उनके गले से सोने की चैन जिसमें ओम का लाकेट लगा है, खिंच कर लें गया। प्रोफेसर ने बताया कि हेलमेटधारी आरोपी उनके पीछे पैदल ही आया, उसने कुछ दूरी पर अपनी बाईक खड़ी कर रखी थी। चैन खिंचते ही वह बाईक स्टार्ट कर निकल गया।

पूर्व विधायक के बंगले में तैनात गार्ड ने की आत्महत्या

कोंडागांव। में पूर्व विधायक के बंगले में सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी कर रहे आरक्षक ने बुधवार की दोपहर को नदी किनारे पेड़ में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही कोंडागांव पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही मामले की जांच में जुट गई है।

मामले की जानकारी देते हुए कोंडागाँव थाना प्रभारी सौरभ उपाध्यक्ष ने बताया कि कोंडागांव के पूर्व विधायक मोहन मरकाम के बंगले में तैनात आरक्षक सम्पत मंडावी निवासी भानपुरी बुधवार को घर ना जाकर ग्राम लंजोड़ा बुकापारा नदी किनारे पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस बात की जानकारी लोगों को तब मिली जब नदी किनारे कुछ लोग गए हुए थे। ग्रामीण ने फांसी के फंदे पर लटके युवक के शव को देखकर तत्काल सरपंच को सूचना दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

हैवान बना पति: पत्नी,बेटा-बेटी पर कुल्हाड़ी से किया वार, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही महिला

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। जिले के करतला में एक शख्स ने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से मां, बेटी और बेटा गंभीर रुप से घायल हो गए हैं। जिन्हें करतला के सामुदायिक स्वास्य केंद्र में उपचार देने के बाद कोरबा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दो शादियां कर रखी हैं, जिसकी वजह से उसका पहली पत्नी से अक्सर विवाद होता रहता था।

आरोपी शरद दास महंत की पहली पत्नी टीका बाई है। जिससे उसकी बेटी टिंकी (22) और बेटा पवन दास (25) है। वहीं दूसरी पत्नी के चक्कर में शरद का पहली पत्नी से अक्सर विवाद होता था, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पहली पत्नी का आरोप है कि पति उसे घर खर्च नहीं देता, जिसके कारण उसका जीना दुश्वार हो गया है। इस मामले को लेकर कोर्ट ने भी आरोपी को फटकार लगाई है। बस इसी बात को लेकर शरद का पत्नी से विवाद हुआ और हिंसक घटना घट गई।

आरोपी है कि शरद लॉकडाउन के समय अपनी पहली पत्नी, बेटी-बेटे को छोड़कर किसी दूसरी महिला के साथ रहने लगा था। वह जब भी बीच-बीच में घर आता था तो अक्सर मारपीट करता था। जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस में की। घायल महिला ने बताया कि जब भी उसका पति जब से दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा है तब से कुछ भी खर्चा नहीं देता। किसी तरह वह अपनी बेटी और बेटे का भरण-पोषण करते आ रही है। दोनों को पढ़ा-लिखा रही है। मामला कोर्ट में चल भी रहा है, दो दिन पहले कोरबा कोर्ट में पेशी हुई थी। जहां कोर्ट ने शरद को खर्चा देने के लिए कहा। इसी बात से वह नाराज था। घायल महिला ने बताया कि जब वह अपनी बेटी और बेटे के साथ किसी काम से जा रही थी तो इसी दौरान शरद ने उनपर हमला कर दिया। किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई, लोगों ने उसे पकड़ा। इस घटना के बाद आरोपी ने खुद को करतला पुलिस के हवाले किया और घटना की जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

घर में सो रहे दंपती पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास बदमाशों ने पहले पति को पीटा फिर वारदात को दिया अंजाम

डोंगरगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां घर में सो रहे पति-पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयाया किया गया। घटना सांकरदाहरा से लगे ग्राम कन्हारपुरी की है। इस घटना में कन्हारपुरी निवासी अशोक लेंझारे (50 वर्षीय) बुरी तरह से झुलस गए हैं। वहीं पत्नी उषा लेंझारे (47 वर्षीय) भी घायल है। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगांव से मेडिकल अस्पताल रेफर किया है। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने गंभीर रूप से घायल अशोक लेंझारे को रायपुर रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही डोगरगांव पुलिस भी जांच में जुट गई है।

बताया गया कि घटना बुधवार की सुबह करीब साढ़े तीन से चार बजे के बीच की है। जब अज्ञात तीन से चार लोगों ने पेट्रोल डालकर अशोक लेंझारे व उषा लेंझारे को जलाने का प्रयास किया। घटना का कारण तो स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन यह जानकारी सामने आयी है कि घायल अशोक लेंझारे गांव में ही चिल्हर में पेट्रोल बेचने का काम करता है। सांकरदाहरा में भी उसकी एक दुकान है। पूछताछ में भी किसी तरह की जानकारी सामने नहीं आयी है।

खबर यह भी है कि पेट्रोल डालकर जलाने से पहले घायल अशोक लेंझारे के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट तक की है। जिसके कारण उसके सिर व अन्य हिस्से में चोंट के गंभीर निशान मिले हैं। मारपीट की घटना को देख पत्नी उषा लेंझारे बीच बचाव कर रही थी, तभी अज्ञात लोगों ने पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी, जिसमें अशोक लेंझारे के साथ उसकी पत्नी उषा भी झुलस गई। हालांकि उषा की हालत सामान्य बताई जा रही है। अशोक की स्थिति गंभीर है। लगभग 70 प्रतिशत से अधिक बर्न होने की जानकारी मिली है।

एक लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, हत्या व आगजनी की घटना में रहा शामिल

बीजापुर। पुलिस ने बताया कि जिले में चलाये जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत बुधवार को कुटरू पुलिस ने ग्राम पेठा से भैरमगढ़ एरिया जैगुर आरपीसी डीएकेएमएस अध्यक्ष पायकु तेलम (38) पुत्र आयतु तेलम निवासी पेठा थाना कुटरू को पकड़ा गया। पकड़े गये नक्सली पर एक लाख रुपये का इनाम है। वह वर्ष 2005 से संगठन में सक्रिय है। उस पर दो स्थाई वारंट लंबित हैं तथा 10 हजार का इनाम उद्घोषित है।

पकड़ा गया इनामी नक्सली पायकु तेलम कुटरू थाना क्षेत्र के मंगा पेटा भैसाबाड़ा के पास 3 मार्च 2022 को हाईवा वाहन में आगजनी, 31 दिसंबर 2022 को दरभा निवासी चैतु माड़वी की हत्या, 20 जून 2023 को पाता कुटरू में सहायक आरक्षक संजय बेड़जा की हत्या व 11 मार्च 2024 को तेलीपेंटा निवासी पुसू तेलम का अपहरण कर हत्या करने की घटना में शामिल था। पकड़े गए नक्सली के खिलाफ कुटरू थाना में वैधानिक कार्यवाही के बाद न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया है।

युवक के हत्या का प्रयास करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, जेल

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। युवक की हत्या का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को सुपेला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में धारा 294, 506, 307, 34 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है। सुपेला टीआई राजेश मिश्रा ने बताया कि पीड़ित राहुल राव निवासी कांट्रेक्टर कालोनी सुपेला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी के मुताबिक 12 जून की सुबह 4.30 बजे अपने काम पर जाने के लिए घर से आकाश गंगा सुपेला जा रहा था। उसी दौरान राहुल गौतम, सुरजीत सिंह और उसके साथी ने रास्ता रोककर उस पर चाकू से वार कर दिया।

आरोपी राहुल गौतम 29 वर्ष निवासी तुलसीपुर बख्तावर चाल राजनांदगांव जो वर्तमान में सुपेला में रह रहा है, उसके साथ सुरजीत सिंह 24 वर्ष निवासी ट्रांसपोर्ट नगर को सुपेला में घेराबंदी का पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपियों के मुताबिक प्रार्थी ने उनके खिलाफ एक दूसरे मामले में पुलिस थाने में शिकायत करने के लिए एक दूसरे व्यक्ति की मदद की थी। उसी का बदला लेने उस पर वार किया।

मरवाही पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ हो रहा था शराब का अवैध परिवहन, 150 पेटी जब्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

मरवाही। मध्यप्रदेश से तस्करी कर छत्तीसगढ़ लाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब की एक बड़ी खेप मरवाही पुलिस को पकड़ने में सफलता मिली है। अंग्रेजी शराब के साथ एक पिकअप वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया है। वही, अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी शराब तस्कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस शराब तस्करों की तलाश में जुटी हुई है।

जानकारी के मुताबिक, मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले से अंग्रेजी अवैध शराब की बड़ी खेप पिकअप वाहन में भरकर मरवाही के रास्ते छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर ले जाई जा रही थी। मरवाही पुलिस की सूझबूझ से अवैध शराब की खेप को पकड़ा गया है। मरवाही पुलिस की टीम रात में गस्त के दौरान दानीकुंडी इलाके में थी, तभी संदिग्ध वाहन दिखा, जिसे रोककर तलाशी ली तो पुलिस के होश उड़ गए। पूरे वाहन में अंग्रेजी शराब भरी थी, उसी दौरान आरोपी जो वाहन में थे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने करीब 150 पेटी शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि यह पूरा माल अंबिकापुर के बड़े शराब तस्कर के द्वारा मंगाया जा रहा था। जो मुखबिर की सूचना के बाद पकड़ लिया गया। फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

भाजपा नेताओं के आरोप के बाद गिरफ्तारी देने पहुंचे पूर्व मंत्री गुरु रुद्र

- **बलौदाबाजार हिंसा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेताओं पर लगाया था आरोप**

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 10 जून को हुई हिंसा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के तीन मंत्रियों ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसे कांग्रेस की साजिश बताया था। भाजपा नेताओं ने पूर्व मंत्री गुरु रुद्रकुमार, देवेन्द्र यादव सहित कई नेताओं पर भड़काने का आरोप लगाया था।

इसके बाद बुधवार को पूर्व मंत्री गुरु रुद्रकुमार अपनी गिरफ्तारी देने एसपी संतोष सिंह के दफ्तर पहुंच गए। हालांकि उस वक्त एसपी ऑफिस में नहीं थे।

बता दें 10 जून को बलौदा बाजार में गिरौधपुरी धाम में जैतखाम तोड़े जाने के विरोध में सतनामी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। इसके बाद मंगलवार देर शाम छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा और श्यामबिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि सतनामी समाज के प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे और पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार, पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया, राज्यसभा की पूर्व सासंद छाया वर्मा, विधायक संदीप साहू, भोजराम अजगले, विधायक इंद्रा साव, पूर्व विधायक भुवनेश्वर बघेल, शिक्षक मोहन बंजारे जैसे नेताओं ने ही लोगों को भड़काने का काम किया।

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा में सरकार के आरोप के बाद पूर्व मंत्री गुरु रूद्र कुमार रायपुर एसएसपी दफ्तर गिरफ्तारी देने पहुंचे हैं। एसपी के अनुपस्थित रहने पर वे काफी देर वहां बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के तीन-तीन मंत्रियों ने उन पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है, इसलिए वे खुद ही गिरफ्तारी देने पहुंचे हैं। गुरु रूद्र कुमार ने यह भी कहा कि इस तरह के आरोप से उनकी व्यक्तिगत छवि धुमिल हुई है और वे तीनों मंत्रियों के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे।

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH, WATER RESOURCES DEPARTMENT OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER MAHANADI GODAWARI BASIN RAIPUR (C.G)

e-PROCUREMENT TENDER NOTICE

eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

CORRIGENDUM No. 01

Following Amendment is made in System Tender No.: 154151/NIT No.: 59/SAC/2023-24, Durg, Dated: 14.03.2023 and 154152/NIT No.: 60/SAC/2023-24, Durg, Dated: 14.03.2023

Ammendment

1. Bid Start Date and time: 18.06.2024, 17:31 Hours
2. Bid Due Date and time: 01.07.2024, 17:30 Hours
3. Bid Open Start Date and time: 02.07.2024, 11:30 Hours.

All other terms and condition will be unchanged.
G.No. 08559

Executive Engineer
Tandula Water Resources Division, Durg (C.G)
For, Chief Engineer, Mahanadi Godavari
Basin Raipur (C.G)

G-242500261/5

खड़ी मिनी पिकअप से भिड़े बाइक सवार, जीजा साले की मौत

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बुधवार की शाम मिनी पिकअप और बाइक की टक्कर से जीजा-साले की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि, दोनों शराब नशे में धुत थे। पुलिस ने शवों का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र के कासनिया मोड़ के पास का है।

जानकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान संतोष चौहान और मनीष चौहान के रूप में हुई है। दोनों रिश्ते में जीजा-साले थे। संतोष चौहान अपने ससुराल मलदा आया हुआ था। जिसके बाद अपने साले के साथ किसी काम से चाम्पा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक सवारों ने खड़ी इलेक्ट्रॉनिक वाहन छोटा पिकअप को साइड से जोरदार टक्कर मार दी। जिससे दोनों लहूलुहान होकर सड़क पर ही गिर गए। सिर पर गंभीर चोट आने की वजह से दोनों की मौके पर मौत हो गई। जिससे घटना स्थल पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई।

हादसे की सूचना कटघोरा पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम घटना स्थल पर पहुंची। शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजवा दिया। शाम होने के चलते आगे की कार्रवाई नहीं हुई। आज गुरुवार को पीएम किया गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि, कासनिया मोड़ पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। मुख्य मार्ग होने के कारण भारी वाहनों की भी आवाजाही काफी बढ़ गई है। भीड़ और रफ्तार की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

-:: नाम परिवर्तन ::-

मैं मो. फैज उम्र 30 साल पिता मो. कौसैन पता संग्राम चौक वृन्दा नगर केम्प-1 सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. का हूँ जो कि निम्नलिखित कथन प्रस्तुत कर रहा हूँ:-

यह कि मै उपरोक्त दर्शाये गये पते पर निवास करता हूँ।

यह कि मेरे पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र नगर पालिक निगम भिलाई से जारी किया गया है जिसमें उसका का नाम मोहम्मद अरहान कादरी MOHAMMAD ARHAAN QADRI दर्ज है ।

यह कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम मोहम्मद अजलान कादरी MOHAMMAD AZLAAN QADRI दर्ज करवाना चाहता हूँ।

यह कि मेरे पुत्र MOHAMMAD AZLAAN QADRI को भविष्य में इसी नाम से जानने, पहचानने, शासकीय/अशासकीय या अन्य संस्थान, जन्म प्रमाण पत्र में इसी नाम को दर्ज किया जाने के समर्थन में यह शपथपत्र प्रस्तुत करना है अत: शपथपत्र प्रस्तुत है।

शपथकर्ता

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग दुर्ग (छ.ग.)

संक्षिप्त मैन्युअल निविदा सूचना क्रमांक-01

ज्ञा.कं. 756 / व.ले.लि./ग्रा.यां.से./2024-25 **दुर्ग, दिनांक 10/6/2024**

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1.	शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह में आर.सी.सी. नाली निर्माण एवं पाईप पुलिया निर्माण कार्य	12.48
2.	शासकीय बालगृह में भवन मरम्मत कार्यालय भवन संधारण कार्य	8.26
3.	Construction of badminton court at Govt. High school Katro	11.16
4.	Shed at cremation ground at village Janjgiri	6.32
5.	Construction of dome shed at school in village Machandur	7.34
6.	Maintenance work at Muskan School, Sector-2	11.90
7.	Laying of paver block at Siyan Sadan	5.19
8.	Repair of CSR office double storied building for Koushal Kutir	19.33
9.	Construction of boundary wall at feel parmarth foundation	17.83
10	Maintenance of water tank at peeparchedi	5.97

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि विस्तृत निविदा विज्ञप्ति निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी http://res.cg.gov.in में अथवा कार्यालयीन अवधि में दिनांक 10/06/2024 से देखी जा सकती है एवं ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 24/06/2024 है।

जी-242500208/4

कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दुर्ग

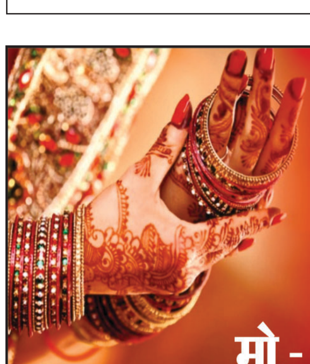
भिलाई की सबसे बड़ी चुड़ी की दुकान
निखार बैंगल
मो.- 9826186026
Shop-47, 'A' Market, Sec-6, Bhilai Nagar, Distt., Durg (C.G.)

भारतीय बैग हाउस

फैंसी स्ट्राली, स्कूल बैग, ऑफिस बैग, सफर बैग, लेपटॉप बैग, फैंसी छतरी, रेनकोट इत्यादि के विक्रेता
कृष्णा टाकीज रोड, बैंक ऑफ बडौदा के बाजू में रिसाली भिलाई, संजय गुप्ता: 93003-77572

भिलाई मसाला उद्योग

शुद्ध कुटे हुए मसाले,पापड़, अचार, बड़ी, जड़ी-बूटी, जचकी का सामान इत्यादि
128, ए- मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, फोन. 2284508, मो. 9826137766

राकेश ट्रेडर्स
विगत 6 वर्षो से यह दुकान पानी टंकी के सामने स्थानांतरित हो गई है।
Dealers
Marbles, Grinight, Black Stone, Nano & Double Charge Verified Tiles Digital Wall & Floor Tiles Cement Coloru etc.

रायपुर रेट पर माल उपलब्ध
Rakesh Sahu
9302443750, 9907127357
Krishna Talkies Road, Beside Hariom Furniture, Risali, Bhilai - 490006

छत्तीसगढ़ शासन

विष्णु के सुशासन से
संवर रहा छत्तीसगढ़

सुशासन और समग्र विकास के

6 माह

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णुदेव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

विकास की नई राह

- कृषक उन्नति से समृद्ध किसान, 3100 रुपए में ख़रीदा धान
- मिला दो वर्षों का 3716 करोड़ रुपए बकाया बोनस
- पीएम आवास से 18 लाख से अधिक परिवारों को अपना मकान, गरीबों का रखा ध्यान
- मुफ्त अनाज से गरीबों का कल्याण, एक करोड़ से अधिक परिवारों को 5 वर्षों तक राशन
- महतारी वंदन से महिलाओं को आर्थिक संबल, प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की मदद से 70 लाख महिलाओं को मिला बल
- तेंदूपत्ता मानदेय अब बढ़कर प्रति मानक बोरा 5,500 रुपए भुगतान, आदिवासी का सम्मान
- शासकीय भर्ती आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिली, युवाओं में चहुँओर खुशी
- भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित, युवा रहेगा अब निश्चिंत
- 'नियद नेल्लानार' से माओवादी समस्या का पूर्ण निदान, लड़ाई से आगे बढ़ विकास का विधान
- त्वरित निर्णय- सख्त प्रशासन, विगत 6 माह में, 129 माओवादी ढेर, 488 गिरफ्तार, 431 आत्मसमर्पण
- 'रामलला दर्शन योजना' से श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा का मिल रहा सौभाग्य

RO-40358/89

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950